राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में प्रेसनोट,नोटिस,वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उत्तरांचल,उत्तराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रकाशित

सुरत–गुजरात,संस्करण बुधवार 08 –नवम्बर–2023 वर्ष–6,अंक–288 पृष्ठ–08 मूल्य–01रूपये

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

महंगाई से लड़ने के लिए सरकार का प्लान, 27 रुपये किलो आटा, 60 रुपये किलो मिलेगी दाल, देशभर में बिक्री शुरू

नई दिल्ली। दिवाली से पहले उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र ने 'भारत आटा' ब्रांड नाम से देशभर में 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं के आटे की बिक्री औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। 'भारत आटा' सहकारी समितियों नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के माध्यम से देशभर में 800 मोबाइल वैन और 2,000 से अधिक दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा। गुणवत्ता और स्थान के आधार पर सब्सिडी वाली दर मौजूदा बाजार दर 36-70 रुपये प्रति किलोग्राम से कम है। फरवरी में, सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के तहत कुछ दुकानों में इन सहकारी समितियों के माध्यम से 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर 18,000 टन 'भारत आटा' की प्रायोगिक बिक्री की थी। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने यहां कर्तव्य पथ पर 'भारत आटा' की 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा, अब जब हमने परीक्षण कर लिया है और सफल रहे हैं, तो हमने एक औपचारिकता पूरी करने का फैसला किया है ताकि देश में हर जगह आटा 27.50 रुपये प्रति किलो की दर पर उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि परीक्षण के दौरान गेहूं के आटे की बिक्री कम थी क्योंकि इसे केवल कुछ दुकानों के माध्यम से खुदरा बेचा गया था। हालांकि, इस बार बेहतर उठान होगा क्योंकि उत्पाद देशभर में इन तीन एजेंसियों की 800 मोबाइल वैन और 2,000 दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस दौरान बताया कि इसके लिए ढ़ाई लाख मीट्रिक टन गेहूं का एलॉकेशन विभिन्न सरकारी एजेंसियों को किया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार अभी देश में आटे की औसत कीमत 35 रुपए किलो है बाजार में नॉन-ब्रांडेड आटे की खुदरा कीमत 30-40 रुपए किलो है तो ब्रांडेड आटा 40-50 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। गेहूं की लगातार बढ़ती कीमत की वजह से त्योहारी सीजन में आटे की कीमत में तेजी को देखते हुए सरकार ने सस्ते दाम पर आटा बेचने का फैसला किया है। प्याज की बढ़ी कीमतों से कंज्यूमर्स को राहत देने के लिए सरकार 25 किलो के रेट से प्याज बेच रही है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCCF और नेफेड 25 किलो के रेट से बफर प्याज पहले से ही बेच रही हैं।

पहले तोड़ी पार्टी और अब खिसका ली जमीन, बारामती में जीरो हुआ शरद पवार गुट; अजित पवार की बड़ी जीत

बारामती में अजित पवार गुट को बड़ी सफलता मिली है। बारामती तालुका की 32 में से 30 ग्राम पंचायतों पर अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट ने कब्जा जमा लिया है। भाजपा का भी यहां खाता खुल गया है।

मुंबई। मराठा छत्रप शरद पवार शायद अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पहले उनके भतीजे अजित पवार ने पार्टी में सेंध लगा दी और जुलाई में कई विधायकों को लेकर डिप्टी सीएम बन बैठे। अब उन्होंने चुनावी मैदान में भी शरद पवार को पहला झटका दिया है। इसमें भी सबसे अहम यह है कि पवार फैमिली के गढ़ कहे जाने वाले बारामती में अजित पवार गुट को बड़ी सफलता मिली है। बारामती तालुका की 32 में से 30 ग्राम पंचायतों पर अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट ने कब्जा जमा लिया है। यही नहीं बाकी 2 सीटें भी भाजपा के हिस्से आई हैं रविवार को महाराष्ट्र में 2,359 ग्राम पंचायतों और 130 सरपंच के पदों पर चुनाव हुए थे। इनमें से 1300 से ज्यादा पदों पर भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी गुट ने जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट को 1000 से भी कम सीटों पर

संतोष करना पड़ा है। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों और सरपंच के चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं होते, लेकिन पार्टियां उम्मीदवारों को अपना समर्थन जरूर देती हैं। ऐसे में बारामती में अजित पवार गुट की बड़ी जीत उनके चाचा शरद पवार के लिए बड़ा झटका है।

● बारामती तालुका की 32 में से 30 ग्राम पंचायतों पर अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट ने कब्जा जमा लिया है। यही नहीं बाकी 2 सीटें भी भाजपा के हिस्से आई हैं रविवार को महाराष्ट्र में 2,359 ग्राम पंचायतों और 130 सरपंच के पदों पर चुनाव हुए थे। इनमें से 1300 से ज्यादा पदों पर भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी गुट ने जीत हासिल की है।

बारामती लोकसभा सीट का एनसीपी की राजनीति में कितना अहम रोल है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 1996 से 2004 तक लगातार शरद पवार यहां से सांसद रहे। उसके बाद से ही लगातार उनकी बेटी सुप्रिया सुले यहां से सांसद हैं। ऐसे में ग्राम पंचायतों के चुनाव में बारामती से शरद पवार गुट की हार उनकी जमीन खिसकने के संकेत के तौर पर भी देखी जा रही है। अजित पवार का साथ आना भाजपा के लिए भी बड़ी सफलता है। उसका यहां खाता खुल गया है। इसके अलावा पहली बार बारामती में उसका सरपंच भी चुना गया है।

चुनाव नतीजों को लेकर भाजपा का दावा है कि उसने 2,359 में से करीब 1000 ग्राम पंचायतों में जीत हासिल की है। दूसरे नंबर अजित पवार गुट की एनसीपी रही है और तीसरे पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना। हालांकि जीत के दावे भी अलग-अलग दिख रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाविकास अघाड़ी ने ज्यादा सीटें हासिल की हैं। चर्चा यह भी है कि बारामती लोकसभा सीट से सुप्रिया सुले के मुकाबले अजित पवार गुट ही उम्मीदवार उतार सकता है। ऐसा हुआ तो यह सुप्रिया सुले के लिए खतरे की घंटी होगा।

एबीवीपी ने भी खेला माइनॉरिटी कार्ड, विश्वविद्यालय के चुनाव में उतारा मुस्लिम प्रत्याशी

● 9 नवंबर को चुनाव होने हैं। दूसरी तरफ एसएफआई-एएसए और टीएसएफ ने गठबंधन करके मोहम्मद अतीक अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव दो अल्पसंख्यकों के बीच ही लड़ा जाएगा।

हैदराबाद। पहली बार किसी विश्वविद्यालय में ऐसा हो रहा है कि आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी ने मुस्लिम को चुनाव में उतारा है। हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी ने इस बार शेख आयेशा को अपना प्रत्याशी बनाया है। 9 नवंबर को चुनाव होने हैं। दूसरी तरफ एसएफआई-एएसए और टीएसएफ ने गठबंधन करके मोहम्मद अतीक अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है।

ऐसे में विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव दो अल्पसंख्यकों के बीच ही लड़ा जाएगा। शेख आयेशा विशाखापट्टनम की रहने वाली हैं और हैदराबाद विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री से पीएचडी कर रही हैं।अहमद भी

पीएचडी के ही स्टूडेंट हैं। बता दें कि हैदराबाद विश्वविद्यालय की राजनीति अकसर चर्चा का विषय रहती है। बता दें कि पिछले साल के चुनाव में एबीवीपी की हार हुई थी। इस बार अल्पसंख्यकों के मुद्दे को भी कवर करने के लिए एबीवीपी ने नया तरीका अपनाया है। एक तरफ दक्षिणपंथी राजनीति और दूसरी तरफ प्रत्याशी का अल्पसंख्यक समुदाय से होना एबीवीपी के लिए फायदे का सौदा हो सकता है।

पिछले साल के चुनाव में एक समलैंगिक दलित उम्मीदवार ने चुनाव जीता था। उनका नाम प्रज्वल गायकवाड़ था। अध्यक्ष पद के अलावा दो अन्य प्रमुख पद भी गठबंधन को ही मिले थे। बता दें कि उससे पहले चार साल तक चुनाव नहीं हुए। 2018 में छात्रसंघ के चुनाव में एबीवीपी की जीत हुई थी।

मैंने अपने नाम पर कोई सड़क या स्टेडियम नहीं बनवाया; ममता बनर्जी ने कसा तंज

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे नाम पर कोई स्टेडियम या फिर रोड नहीं है। ममता बनर्जी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी पर उन्होंने तंज कसा है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की ओर से कई स्कीमों के लिए फंड न जारी किए जाने पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने भवानीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। ममता ने कहा कि मेरे नाम पर कोई स्टेडियम या फिर रोड नहीं है। ममता बनर्जी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी पर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को 100 दिनों के काम के बाद भी पेमेंट नहीं मिल पा रही है। ममता ने कहा, हमें मनरेगा के लिए फंड नहीं मिल रहा है। पीएम आवास और सड़क योजना के लिए भी केंद्र सरकार की ओर से फंड अटका है।

उन्होंने कहा दुर्गा पूजा के एक

आयोजन में कहा कि हम सद्भाव और धार्मिक एकता का संदेश दे रहे हैं। हम विभाजनकारी राजनीति नहीं करते। यहां किसी से भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता और सभी को साथ लेकर चलते हैं। पूरी दुनिया ही वैश्विक ग्राम है। मैं अपनी जन्मभूमि से प्यार करती हूं। इसलिए मैं ज्यादातर चुप ही रहती हूं और किसी भी नेता पर निजी हमले नहीं करती। उन्होंने कहा कि यह धरती तो संस्कृति, एकता और सद्भाव की है। यही वह धरती है, जहां से आजादी का संघर्ष शुरू हुआ था। सीएम ने कहा कि देश की आजादी के संघर्ष में बंगाली और सिख समुदाय ने अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया था।

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बंगाल में टीएमसी मुश्किलों का सामना कर रही है। एक तरफ राशन घोटाले के आरोप में ज्योतिप्रिय मलिक को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है तो वहीं महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसदीय समिति जांच कर रही है। उन पर कैश के बदले सवाल पूछने का आरोप लगा है। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है और उनसे पूछताछ भी की जा चुकी है। इसके अलावा कई अन्य मंत्री भी अरेस्ट हो चुके हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार के मामलों में घिरी टीएमसी क्या रणनीति अपनाएगी, यह देखने वाली बात होगी।

राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 2605 उम्मीदवारों ने किए नामांकन पत्र दाखिल

जयपुर। राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य के सभी दो सौ विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2605 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं जिनमें करीब तीन सौ महिला प्रत्याशी शामिल है।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन 1543 उम्मीदवारों ने 1974 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। प्रदेश में चुनाव के लिए गत 30 अक्टूबर को नामांकन भरना शुरू किया गया और इसके आखिरी दिन छह नवंबर तक कुल 2605 उम्मीदवारों ने 3436 नामांकन पत्र भरे। इस दौरान 299 महिला उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पर्चा भरा। गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में सबसे अधिक 31 उम्मीदवारों ने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में नामांकन भरे। इसके बाद कामां में 28, आहोर और भीलवाड़ा में 27-27 और अजमेर उत्तर, साँगानेर और सूरसागर में 26 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। सबसे कम 4-4 उम्मीदवारों ने दूदू और लालसोट में, चोहटन में पांच उम्मीदवारों ने और रेवदर एवं चाकसू विधानसभा क्षेत्रों में 6-6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच सात नवम्बर को पूर्वाह्न 11 बजे से रिटर्निंग अधिकारी के

कार्यालय में ऑब्ज़र्वर की उपस्थिति में होगी और नामांकन वापसी की अंतिम तारीख नौ नवम्बर है। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान 25 नवम्बर को प्रातःसात बजे से शाम छह बजे तक होगा जबकि मतगणना तीन दिसंबर को होगी।

उन्होंने बताया कि इन उम्मीदवारों में 408 प्रत्याशियों ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी दी।

अंधेरे में रखा गया और नियम किनारे लगा दिए; सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर भड़के अधीर रंजन चौधरी

नई दिल्ली। हीरालाल सामरिया देश के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं और वह दलित समुदाय से आने वाले पहले व्यक्ति हैं, जिन्हें यह अहम पद मिला है। लेकिन उनकी नियुक्ति को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने वाली समिति के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खत लिखकर कहा है कि उन्हें इस नियुक्ति को लेकर पूरी तरह अंधेरे में रखा गया। अधीर रंजन चौधरी पीएम की अध्यक्षता वाली उस समिति का हिस्सा हैं, जो मुख्य सूचना आयुक्त का चयन करती है। उन्होंने कहा कि इस नियुक्ति के बारे में सरकार ने उन्हें न तो कुछ बताया और न ही सलाह ली गई। अधीर रंजन चौधरी ने अपने पत्र में लिखा, यह बेहद दुख का विषय है। मैं भारी मन से आपको लिख रहा हूं कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में सभी

लोकतांत्रिक प्रावधान, नियम और प्रक्रियाओं को किनारे रख दिया गया। सामरिया ने सोमवार को ही मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही शपथ दिलाई थी। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। अधीर रंजन से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें मीटिंग के बारे में बताया गया था। लेकिन फिर वह स्थगित हो गई और तारीख बदली गई। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी कोलकाता चले गए और जब वह वापस लौटे तो पचा चला कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है। इस बारे में उन्हें बताया भी नहीं गया। सूचना का अधिकार कानून के मुताबिक मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति के मुखिया पीएम होते हैं और उसमें सदस्य के तौर पर एक केंद्रीय मंत्री एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल किया जाता है। अधीर रंजन ने अपने पत्र में दावा किया है कि कार्मिक विभाग ने उनसे अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में संपर्क किया था। इस दौरान उनसे पूछा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर कमेटी की मीटिंग होनी है, आप कब उपलब्ध होंगे। चौधरी ने कहा कि मैंने बताया कि 2 नवंबर तक दिल्ली में रहूंगा और उसके बाद 3 तारीख को कोलकाता में एक कार्यक्रम में शामिल होना है। इस पर उन्हें जानकारी मिली कि अब 3 नवंबर को शाम 6 बजे मीटिंग होगी। अधीर रंजन ने कहा कि मैंने कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह से अपील की थी कि मीटिंग को रिशेड्यूल कर दिया जाए। हालांकि उन्हें बाद में यही पता चला कि हीरालाल समारिया को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है।

प्रदूषण वाले लॉकडाउन की ओर बढ़ रही दिल्ली? 16 गुना ज्यादा जहरीली हवा में सांस ले रहे राजधानी के लोग

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के लोग गंभीर स्तर की जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों से सोलह गुना ज्यादा प्रदूषित हवा सांसों पर संकट खड़ा कर रही है। सोमवार शाम तीन बजे दिल्ली की हवा में प्रदूषक कण पीएम 2.5 का स्तर 243 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा, जो डब्लूएचओ के मानक से सोलह गुना से भी ज्यादा है। हवा में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि लोग आमतौर पर ही आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, नाक और गले में खराश जैसी शिकायतें कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, हवा में पीएम 2.5 का स्तर 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पीएम 2.5 का स्तर इससे ज्यादा है तो वह हवा स्वास्थ्यकारी नहीं है। अगर इन मानकों पर दिल्ली की हवा को परखा जाए तो अभी राजधानी की हवा में सोलह गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। हालांकि, भारतीय मानकों के अनुसार हवा में पीएम 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए। इस अनुसार भी दिल्ली की हवा में सामान्य से चार गुना ज्यादा प्रदूषक कण हैं।

विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र में वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ अविकल बताते हैं कि अपने देश के भौगोलिक कारकों और जलवायु के अनुसार अलग-अलग देशों ने अलग मानक तैयार किया है।

अगले तीन दिन तक राहत के आसार नहीं-राजधानी दिल्ली के लोगों को अभी प्रदूषण से

राहत मिलने की संभावना नहीं है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक अगले तीन दिनों के बीच हवा की रफ्तार मुख्यत दस किलोमीटर प्रति घंटे से कम रहने और हवा की दिशा उत्तरी पश्चिमी रहने का अनुमान है। इसके चलते प्रदूषक कणों का बिखराव भी धीमा रहेगा। मौसम के इन कारकों के चलते अगले तीन दिनों के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में ही बने रहने की आशंका है।

पांच सौ से ऊपर सूचकांक की नहीं होती गणना-देश में आठ मानकों के आधार पर वायु गुणवत्ता सूचकांक तैयार किया जाता है। इनमें पीएम 10, पीएम 2.5, नाइट्रोजन डाई आक्साइड, कार्बन मोनो आक्साइड, लेड, अमोनिया, ओजोन और सल्फर डाई ऑक्साइड शामिल हैं। इस आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) 500 तक वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना करता है। पांच सौ से ऊपर की गणना सीपीसीबी द्वारा नहीं की जाती है।

धूप निकलने से एक अंक नीचे आई वायु गुणवत्ता-दिल्ली में सोमवार को दिनभर धूप खिली रही। इससे प्रदूषक कणों का बहाव थोड़ा तेज हुआ है और प्रदूषण के स्तर में भी थोड़ा सुधार हुआ। हवा अत्यधिक गंभीर श्रेणी से एक स्तर नीचे आकर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। वातावरण में मौजूद नमी के चलते पिछले कुछ दिन से हल्की धुंध देखने को मिल रही थी। नमी के साथ मिलकर प्रदूषण की परत स्मॉग बना रही थी। धूप भी तेज नहीं हो रही थी, लेकिन अब नमी कम होने के साथ ही सोमवार को नौ बजे के बाद से ही खिली हुई धूप निकल आई। दिनभर धूप निकलने के चलते प्रदूषक कणों का बिखराव भी पहले से तेज हुआ।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

बार-बार भूकंप

नेपाल और उत्तर भारत में बार-बार भूकंप के झटकों से चिंता का माहौल है। सोमवार को आया ताजा झटका रिक्टर स्केल पर 5.6 का रहा, जबकि शुक्रवार रात आया झटका 6.4 तीव्रता का था। नेपाल में शुक्रवार 3 नवंबर को आए भूकंप की वजह से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। भारत ने भी राहत राशि नेपाल भेजी है और वहां बचाव कार्य जोर-शोर से चल रहा है। सोमवार शाम को आए झटके से नेपाल में विशेष रूप से चिंता की लहर है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र उत्तर प्रदेश में अयोध्या से 233 किलोमीटर उत्तर में था। वास्तव में, नेपाल की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां आने वाला कोई भी भूकंप भारत को अवश्य प्रभावित करेगा। 'नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी' के वैज्ञानिक संजय कुमार प्रजापति के अनुसार, ताजा भूकंप 3 नवंबर को आए भूकंप का अगला झटका है। वैसे अब तक 14 छोटे झटके आ चुके हैं। किसी बड़े भूकंप के समय छोटे-छोटे झटके आते हैं। सोमवार को दिल्ली में भी 10 सेकंड तक झटके महसूस किए गए हैं। आशंकाओं का बाजार गरम है, क्या 3 नवंबर को नेपाल में आया 6.4 तीव्रता भूकंप ही मुख्य था और उसके बाद लग रहे छोटे-छोटे झटके उसका असर हैं? दरअसल, विज्ञान अभी इस स्थिति में नहीं है कि भूकंप पर कोई पुख्ता अनुमान लगा सके। अफसोस, नेपाल के जाजरकोट में ज्यादा जनहानि हुई है और इससे बाकी नेपाल में भी दुख का माहौल है। नेपाल में बचाव के सभी उपाय किए जा रहे हैं और कमजोर इमारतों से लोगों को हटाया भी गया है। नेपाल के लोगों के मन में साल 2015 में आए भूकंप की यादें ताजा हो आई हैं। उस आपदा में करीब 9,000 लोग मारे गए थे। तब कई कस्बे, सदियों पुराने मंदिर और अन्य ऐतिहासिक स्थल मलबे में तब्दील हो गए थे और दस लाख से अधिक घर नष्ट हो गए थे। नेपाल को उस वक्त लगभग छह अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। नुकसान इस बार भी बहुत हुआ है और अभी कुल अनुमान लगाया जा रहा है। नेपाल में चूंकि सर्दियों के दिन शुरू हो चुके हैं, इसलिए चिंता ज्यादा है। भारत को नेपाल की हरसंभव मदद करनी चाहिए। ऐसे भूकंपों को न्यूनतम नहीं किया जा सकता, मगर उनसे होने वाले नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाएं हर साल औसतन 20 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करती हैं और दो करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हो जाते हैं। दक्षिण एशिया के देशों को तो विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हिमालय से लगा हुआ पूरा इलाका भूकंप संवेदी है। हिमालय से सटे तमाम देशों को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अपनी अलग व्यवस्था भी करनी चाहिए। यह व्यवस्था दक्षेस के मंच से भी हो सकती है। आपदा के समय दक्षिण एशिया के देश एक-दूसरे के ज्यादा काम आ सकें, सूचनाएं साझा कर सकें, एक-दूसरे को बचाव सामग्री मुहैया करा सकें, इसके लिए पुख्ता तौर पर साझा आपदा प्रबंधन ढांचा तैयार रखना चाहिए। बेहतर सहयोग के लिए परस्पर विवादों से ऊपर उठना जरूरी है। भारत इस दिशा में आगे बढ़कर पहल कर सकता है। ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए दक्षिण एशिया के देशों को अपनी आर्थिक स्थिति में परस्पर बेहतर समन्वय के साथ सुधार करना होगा। इन देशों में परस्पर बेहतर संबंधों की बड़ी जरूरत है। निस्संदेह, बार-बार आ रहे झटके किसी चेतावनी से कम नहीं हैं।

आज का राशीफल

मेष व्यावसायिक योजना को बल मिलेगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें, दुर्घटना की आशंका है।

वृषभ सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी अपेक्षित है।

मिथुन जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। चली आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

कर्क आर्थिक दृष्टि से लाभदायी है। व्यावसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। स्थानान्तरण का भी लाभ मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा।

सिंह व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्थानान्तरण सुखद हो सकता है। नई नौकरी या नवीन वाहन का सुख मिल सकता है। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। प्रणय प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा।

कन्या आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा।

तुला पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। संबंधित अधिकारी या घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

वृश्चिक जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। विरोधी सक्रिय होंगे। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी।

धनु राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें चोरी या खोने की आशंका है। नेत्र विकार की संभावना है। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा।

मकर व्यावसायिक योजना सफल होगी। रोजी रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। वाद विवाद की स्थिति कष्टकारी होगी। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा।

कुम्भ आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आपकी राशि से आठवें शनि यात्राएं देगा व थकान देगा। किसी वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका है। दूसरों से सहयोग लेने में सफल होंगे। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। धन व्यय होगा।

मीन आर्थिक योजना फलीभूत होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी अपेक्षित है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। निजी सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी।

पहचान नहीं, मानवता से परिभाषित हो नैतिकता

राजेश रामचंद्रन

'जहां तक हमास की बात है, उसे और उसके समर्थकों को इंसानियत अपनी बिरादरी से निकाल बाहर करे'- ये शब्द टाइम्स पत्रिका के नवीनतम अंक में मशहूर इतिहासकार और 'सेपियन्स' के लेखक नोह हरारी ने लिखे। बतौर एक इस्राइली उन्होंने माना कि यह घड़ी पीड़ादायक है- पहले हमास आतंकियों द्वारा इस्राइली आम नागरिकों पर किया गया हमला और फिर इस्राइलियों द्वारा बेगुनाह फलस्तीनी नागरिकों पर क्रूर प्रतिकर्म- जिसमें एक समूह दूसरे को और अधिक कष्ट देने में लिहाज नहीं कर रहा। सामूहिक पहचान के नाम पर हुई तमाम साम्प्रदायिक और कबीलाई लड़ाइयों का यही दुखांत रहा है। एक समुदाय के ज़हन में दूसरे को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति इस कदर भर जाती है कि यह भी नहीं देखता कि दूसरे को कितनी पीड़ा होगी। हरारी चाहते हैं कि वे 'बाहरी लोग जो खुद पीड़ा में न डूबे हों', शांति के लिए जगह बनवाएं ताकि 'एक दिन जब जख्म भर जाएं, तो इस्राइली और फलस्तीनी, दोनों उस जगह पर बस सकें'। शांति के लिए वह स्थान केवल तभी बन सकता है जब समुदायों के बीच सह-अस्तित्व हो, जहां नफरत की जगह दूसरे से सहचर की भावना हो। लेकिन जहां नफरत ही राजनीति और प्रशासन चलाने का प्रमुख आधार हो, तब परस्पर शिकायतों से भरे दो समुदायों के बसने के लिए साझी जगह कभी नहीं बन सकती। हमास और इस्राइली सरकार एक जैसे हैं, जिनका जीवन-मरण दूसरे से घृणा करने पर टिका है। जिस पक्ष को पश्चिमी जगत की मदद मिले, उसका वर्चस्व रहता है। घृणा की प्रतिस्पर्धा में, विशुद्ध मानवता के गुण ही सह-अस्तित्व का माहौल बना सकते हैं, चाहे यह शिकायतकर्ता हो या आक्रमणकारी - हालांकि वे दशकों और सदियों से एक-दूजे की दर्पण-छवि हैं यानि जिसके हाथ जब ताकत आई, दूसरे पर हावी हो गया। दुर्भाग्यवश, किसी जनजाति या साम्प्रदायिक समूह की शिकायतें व्यापक भू-राजनीतिक ताकतों के खेल में एक औजार बन जाती हैं। यह अवस्था उन भारतीयों के लिए जानी-पहचानी है जो आज भी ब्रितानी हुक्मरानों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन को भटकाने अथवा हराने के लिए पैदा की गई हिंदू-मुस्लिम रंजिश की लकीरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। फिर भी, इस्राइल-फलस्तीन संघर्ष ने जिस कदर तीव्र संकट पैदा किए हैं, इसके संदर्भ में, उस शख्स की याद फिर से हो आई है जिसने 'शांति के लिए स्थान' बनाने का प्रयास किया था। बंटवारे के दुःख को लेकर हरारी के पक्षपाती विचारों से उलट, ब्रितानी हुकूमत द्वारा पैदा किए विभाजन के सबसे बुरे दिनों की पीड़ा में डूबे होने के बावजूद गांधी ने हिंदू और सिखों से साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने में पहलकदमी करने को कहा था। वर्ष 1948 में गांधी से अपना आमरण अनशन त्यागने का अनुरोध करने वाले पत्र पर दो लाख लोगों ने हस्ताक्षर करके प्रण लिया : 'हम हिंदू, सिख, ईसाई और दिल्ली के अन्य नागरिक, शपथपूर्ण घोषणा करते हैं कि भारतीय गणराज्य के मुस्लिम नागरिक भी दिल्ली के बाकी बाशिंदों की भांति शांति, सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ जीने और रोजगार करने को स्वतंत्र हैं और भारतीय गणराज्य की भलाई एवं बेहतरी के लिए काम कर पाएंगे'। यह शांति-प्रतिज्ञा भारतीय संविधान लिखे जाने से पहले आई, जिस वक्त यह उपमहाद्वीप लगभग 10 लाख हिंदू, सिखों और मुस्लिमों के खून और तकरीबन एक करोड़ बेघर हुए लोगों की मुसीबतों में अभी भी डूबा पड़ा था। संविधान को बनाए रखने की दुहाई देने वाले हरेक लोकतांत्रिक शख्स को ठिठककर अपनी आत्मा को टटोलना चाहिए, क्योंकि यह उस 78 वर्षीय कृषकाय वृद्ध की देन है, जिसने इंसानियत को सर्वप्रथम और पहचान को अंतिम रखा। पीड़ा और साम्प्रदायिक संताप पर पक्षपाती रुख रखने से केवल नफरत की लकीर पुष्ट होती है, जोकि साम्राज्यवादियों की ईजाद है - नए हों या पुराने। यहां तक कि सबसे खराब घड़ी में भी गांधी जी ने, यह जानते हुए भी कि हिंसक आग के दरिया को पार करके, शरणार्थी बनकर पहुंचे हिंदू-सिखों के संताप के लिए गलती केवल ब्रिटिश और जिन्ना की है, दिल्ली में शांति स्थापना के लिए रखी सात शर्तों पर इन दोनों कौमों को राजी कर लिया था। परस्पर शक की बिना पर एक-दूसरे से टकराने वाले गुटों पर केवल सार्वभौमिक नैतिकता एवं मानक गुण ही लागू हो सकते हैं और इस सार्वभौमिक नैतिकता के मानकों का विशुद्ध मापदंड है सर्व-हितकारी मानवता। अफसोस कि, वे सब जो भारत में फलस्तीनियों के मुद्दे पर एकतरफा रुचि ले रहे हैं, वे पहचान के आधार पर बदतरीन पक्षपात दिखा रहे हैं, जिसमें गैर-साम्प्रदायिक मानवीय सदाशयता की जरा परवाह नहीं है। हाल ही में दक्षिण भारत में हुई दो घटनाएं अति चिंतनीय हैं। एक में, तिरूवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने जब युद्ध विरोधी रैली में हमास को आतंकी संगठन बताया तो उन्हें टोककर इसे सही करने को कहा गया। इसके तुरंत बाद हमास के पूर्व मुखिया माशल ने जमात-ए-इस्लामी की युवा शाखा को ऑनलाइन या पूर्व रिकॉर्डिड संबोधन दिया। भारत के प्रत्येक स्वयंभू तरक्कीयाफ्ता मुस्लिम और मार्क्सवादी नेताओं को यह समझना होगा कि जब वे पश्चिम एशिया में चल रहे नृशंस संघर्ष में हमास की तरफदारी करते हैं तो यह करते वक्त वे अपनी नैतिकता और इंसानियत को त्याग रहे हैं। एक-दूजे का समूल नाश करने के लिए बच्चों की क्रूर हत्याएं, बेगुनाह आम नागरिकों के नृशंस कत्ल, महिलाओं को अगवा या बलात्कार करने के वहशी कृत्यों को केवल आतंकवाद ही कहा जाएगा। यदि हमास 1400 इस्राइलियों को मारने और 200 को बंधक बनाने को इसलिए न्यायोचित बताता है कि वे सब यहूदी थे, तब तो नस्लभेदी इस्राइल सरकार द्वारा गाज़ा को नेस्तनाबूद करने और 10000 फलस्तीनी मारने को सही करार दिया जाएगा। जैसा कि सबका कयास है, इस्राइली खुफिया विभाग ने खुद ही हमास को लुभाकर जाल में फंसाया होगा ताकि गाज़ा का सम्पूर्ण विनाश सुनिश्चित हो सके। अंत में, हमास की सफलता केवल यही कही जाएगी कि उसने अस्पतालों और शरणार्थी कैम्पों पर बमबारी करने की इस्राइली हरकतों को वैधता दे डाली। कुल मिलाकर हमास फलस्तीनियों के लिए तबाही का बड़ा कारण सिद्ध हुआ है। भारतीय मुस्लिम लीग के जिस नेता ने शशि थरूर को टोककर यह कहने को कहा कि हमास 'प्रतिक्रियावादी लड़ाके' हैं, इसके पीछे की वजह है, उनका मुस्लिम हम-बिरादर होना। जमात-ए-इस्लामी संगठन की बात करें, जिसने हमास के नेता का रिकॉर्डिड या ऑनलाइन संबोधन आयोजित किया, तो उसने भी यह पीड़ितों के प्रति मानवता से बंधकर नहीं बल्कि धार्मिक पहचान के आधार पर किया है- इस तथ्य पर कि वे भी मुस्लिम हैं और हमास वाले भी। यहां वे यह समझने में नाकाम रहे हैं कि पहचान की संबद्धता के इस तर्क के आधार पर अगर वे यहूदी पैदा हुए होते, तब क्या इस्राइली सरकार के साथ खड़े होते? एक मुस्लिम के बरक्स यहूदी की जान को तुच्छ समझने वाले ऐसे विचारों का गंभीर असर भारतीय राजनीति पर हो सकता है। मुसीबत के वक्त भी केवल धार्मिक पहचान के आधार पर पाला पकड़ना, नैतिकता का इससे निम्न स्तर नहीं हो सकता। तमाम वे राजनीतिक दल जो इस प्रकार की धार्मिक पहचान के आधार पर वोट पाने को कहते हों, यह बच्चों के कातिलों को संत बनाने की उनकी कुत्सित कोशिशों को उजागर करता है। हमास से किनारा, इस्राइली सरकार की भर्त्सना और सह-अस्तित्व के लिए द्वि-राष्ट्र आधारित हल का आह्वान होना चाहिए न कि किसी का समर्थन अथवा आलोचना इसलिए हो कि वह अपने या पराये धर्म का है!

लेखक प्रधान संपादक हैं।

सामूहिक जवाबदेही में प्रदूषण का समाधान

ज्ञानेन्द्र रावत

देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भीषण प्रदूषण की चपेट में है। विडंबना है कि ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू होने के लगभग 30 दिन बाद भी प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। ग्रैप के नियम टूट रहे हैं, धुआं या धूल उड़ाने, कूड़ा जलाने, निर्माणाधीन इमारतों पर प्रदूषण फैलाने पर 200 से लेकर 50 हजार रुपये के जुर्माने की घोषणा के बाद भी एजेंसियां गंभीर नहीं हैं। इसका नतीजा खांसी, जुकाम, अस्थमा, सांस लेने में परेशानी, गठिया, जोड़ों के दर्द के रोगियों की अस्पतालों में बाढ़ आ गई है। डाक्टरों की मानें तो प्रदूषण धीमा ज़हर है। एम्स के रूमैटोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. उमा कुमार एक शोध का संदर्भ देते हैं कि वातावरण में पीएम 2.5 का स्तर बढ़ने से शरीर में सूजन वाले मार्कर बढ़ जाते हैं। गठिया और आटोइम्यून बीमारी बढ़ जाती हैं। इसलिए गठिया के मरीजों को सतर्क रहना चाहिए। घर से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल श्रेयस्कर है। इंटर्नल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट डॉ. सुरनजीत चटर्जी के मुताबिक प्रदूषण के साथ अब सुबह ठंड का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। ठंड के साथ प्रदूषण बढ़ना ज्यादा खतरनाक है। इससे दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं। असलियत यह है कि सामान्य मास्क से वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कण नहीं रुक पाते। अधिक प्रदूषित जगह पर प्यूरीफायर लगा लेना उचित रहता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई के दावे कुछ भी किये जायें, हकीकत में ज़हरीली हवा में सांस लेना दिल्ली के लोगों की नियति बन चुकी है। मौसम विभाग और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मानें तो फिलहाल प्रदूषण में राहत मिलने के आसार न के बराबर हैं। बोर्ड के अनुसार देश के 227 शहरों के एयर इंडेक्स का जायजा लें तो ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम व नोएडा सबसे अधिक प्रदूषित हैं। इस दौरान वातावरण में पीएम-10 का स्तर 288 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर रहा जो सामान्य से तीन गुणा अधिक है। कहने को तो दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने की दिशा में ग्रीन एप के माध्यम से विशेष अभियान चलाने, ग्रैप के विभिन्न चरणों को लागू कर इसे कम करने, हरित क्षेत्र बढ़ाने को लाखों पेड़ लगाने, 1700 से ज्यादा कंपनियों में सीएनजी और पीएनजी का इस्तेमाल, दो कोयला आधारित संयंत्र बंद किये जाने और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाये जाने से रोकने के लिए केन्द्र के साथ लगातार बैठकें करने और पराली गलाने को मुफ्त बायोडीकंपोजर का छिड़काव करवाने का दावा कर रही है। लेकिन सवाल यह कि इन कोशिशों के बावजूद प्रदूषण से दिल्ली वालों को राहत क्यों नहीं मिल रही है। लाख पाबंदियों और उपायों के बावजूद प्रदूषण के मामले में दिल्ली शीर्ष पर बनी है। डब्ल्यूएचओ की मानें तो दिल्ली वायु गुणवत्ता की सुरक्षित सीमा से 20 गुणा तक अधिक प्रदूषित है। विशेषज्ञों की मानें तो दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण में पराली की अहम भूमिका है। बीते 48 घंटों में ही पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं। फिलहाल पंजाब-हरियाणा की ओर से दिल्ली में उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चल रही है जो पराली जलाने का धुआं दिल्ली ला रही है। अगले 15 दिनों तक इन राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं और बढ़ेंगी। नतीजन पराली का धुआं दिल्ली की ओर आयेगा और प्रदूषण बढ़ेगा। जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल हरियाणा व पंजाब के मुख्यमंत्रियों से पिछले दिनों पराली का प्रदूषण रोकने का अनुरोध भी कर चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस साल 15 सितंबर से 11 अक्तूबर तक हरियाणा में पराली जलाने की 340 घटनाएं हुईं जबकि पिछले साल इस दौरान 83 मामले सामने आये थे। पंजाब में इस अवधि में 1063 घटनाएं हुईं जबकि पिछले साल इस अवधि में 763 घटनाएं हुईं। इसी वजह से दिल्ली सरकार केन्द्र से उत्तर भारत के मुख्यमंत्रियों और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग कर रही है। आम आदमी पार्टी की मांग है कि बैठक में उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों व पर्यावरण मंत्रियों को बताया जाये कि उनके प्रदेशों से किन-किन कारणों से दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है। यदि एनसीआर के सभी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आ जाये तो दिल्ली में इसका सकारात्मक प्रभाव होगा। यह तभी संभव है जब संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री किसानों के साथ बैठक कर बातचीत के जरिये पराली जलाने की घटनाएं रोकने के बाबत प्रयास करें। यह भी सच है कि दिल्ली के चारों तरफ 300 किलोमीटर के दायरे में प्रदूषण से हालात बदतर हैं। दिल्ली में 70 फीसदी प्रदूषण आसपास के क्षेत्रों से आ रहा है। एनसीआर में करीब दो हजार ईंट भट्टे पुरानी तकनीक से और तीन हजार उद्योग कच्चे ईंधन से चल रहे हैं। यहां इस सच्चाई को झुठला नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने भी बीते 10 सालों में बार-बार कहा कि भट्ठा संचालकों के साथ बैठक कर नयी तकनीक से संचालन के लिए प्रोत्साहित करें लेकिन आज तक किसी ने इस बाबत पहल नहीं की। दिल्ली तभी प्रदूषण मुक्त हो सकती है जब नेतृत्व की इच्छाशक्ति हो और संबंधित सरकारें वायु प्रदूषण के नुकसान को समझें और उसके निराकरण के लिए मिलकर ठोस-कारगर उपाय हेतु प्रयास करें। नागरिकों को भी जिम्मेदारी का अहसास हो।

विचार मंथन

राज्यपालों के आत्मचिंतन में स्वामी भक्ति?

(लेखक- सनत जैन)

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने एक याचिका पर राज्यपालों की भूमिका को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीस ने राज्य सरकारों द्वारा सदन में पारित बिलों को राज्यपालों द्वारा स्वीकृत नहीं देने को आपत्तिजनक कृत्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल स्वयं आत्म चिंतन करें। राज्यपाल को जनता ने नहीं चुना है। जनता के प्रति निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। सभी राज्यपालों को मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करना होता है। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार द्वारा सदन से पारित बिलों को राज्यपाल काफी लंबे समय तक के लिए रोक कर रखते हैं। जब सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट की ओर रूख करती है। उसके बाद ही बिलों को स्वीकृति दी जाती है। इस प्रथा को सुप्रीम कोर्ट ने काफी आपत्तिजनक माना है। कुछ राज्यपालों ने सदन से पारित मनी बिलों को भी रोकने का काम करके राज्य सरकारों की आर्थिक गतिविधियों रोकने का प्रयास किया है। जबकि मनी बिल को रोकने का कोई भी अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता है। हाल ही में पंजाब विधानसभा के सत्रावसान को लेकर एक नया विवाद पैदा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान यह भी कहा कि लोकतंत्र की सबसे पुरानी व्यवस्था भारत की है। उसके बाद भी इस तरीके के विवाद राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच हों, यह बहुत चिंतनीय स्थित है। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब इत्यादि राज्यों में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच में भारी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका पर जो कहा है, वह काफी महत्वपूर्ण है। पिछले 5-7 सालों से राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच के संबंध में राजनीति देखने को मिल रही है। केंद्र के इशारे पर राज्यपाल जहा गैर भाजपाई सरकारें हैं। वहॉ के राज्यपाल संबंधित राज्य सरकारों के हर काम को रोकने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल अपने आप को केंद्र का प्रतिनिधि मानते हुए, केंद्र सरकार के राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय करने लगे हैं। जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे चिंताजनक स्थिति है। पिछले 70 वर्षों से राज्यपालों की जो भूमिका थी, वह बहुत सीमित थी। सदन से जो बिल पास होते थे, उसमें राज्यपाल का कार्यालय यह देखता था, कि कोई ऐसा बिल तो पास नहीं हुआ है। जो केंद्रीय कानून और संविधान में वर्णित नियमों के विपरीत कोई प्रावधान किया गया हो। यही देखने की जिम्मेदारी राजभवन की होती थी। आमतौर पर सदन से जो बिल पारित किए जाते हैं। उसमें सरकारों की जिम्मेदारी होती है, कि वह ऐसा कोई कानून पास ना करें। इसको देखने की जिम्मेदारी विधानसभा सचिवालय की भी होती है। विधानसभा सचिवालय बखूबी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए काम करती हैं, और सदन से बिल पारित कराती हैं। पारित बिल को ही राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। सदन से पारित बिलों को राज्यपाल अपने पास ही उसे रोक लेते हैं, अनुमति नहीं देते और कारण भी नहीं बताते है कि अनुमति क्यों लंबित हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यपालों द्वारा मनी बिल के पारित बिलों को भी स्वीकृति देने में काफी विलम्ब किया गया। महाराष्ट्र में तो बड़ा गजब हो गया। विधान परिषद के जिन सदस्यों के लिए सरकार ने नामों की अनुशंसा की, राज्यपाल ने उन्हें ही कई महीनों तक रोक लिया। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा लग रहा है कि निर्वाचित मुख्यमंत्री के ऊपर राज्यपाल का नियंत्रण हो गया है। राज्यपाल जो चाहते हैं, वही करना मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का दायित्व है। इस तरह का दबाव राज्य सरकारों के ऊपर राज्यपाल बनाते हैं। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में कई महीनो तक राज्यपाल की भूमिका चर्चाओं में बनी रही। उसके बाद अब पंजाब, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, दिल्ली इत्यादि राज्यों के राज्यपाल भी टकराव की मुद्रा में रहते हुए, समानांतर सत्ता चलाना चाहते हैं। तमिलनाडु में राज्यपाल ने 12 बिलों को रोक रखा है। केरल के राज्यपाल ने तीन बिलों को 2 साल से और तीन बिलों को 1 साल से ज्यादा समय रोक रखा है। तेलंगाना के राज्यपाल ने 10 बिल 1 साल से रोक रखे हैं। जब दबाव बना, तब उन्होंने मुश्किल से तीन बिल स्वीकृत किए हैं। पंजाब सरकार के कई बिल राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने महीनों से रोक रखे हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार अथवा राज्यपाल की सर्वोच्चता को लेकर भी विवाद खड़े होना शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्पष्ट निर्णय देने की जरूरत है। दिल्ली सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर किया था। उसे मानने के स्थान पर नया कानून बना दिया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली में लागू नहीं हुआ। दिल्ली के उपराज्यपाल जो दिल्ली में कर रहे थे। वहीं अन्य राज्यों के राज्यपाल जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है। इसी तरह की अड़ंगेबाजी करके राज्यपाल अपने आप को सर्वोच्च बता रहे हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

दिवाली से पहले सरकार ने गन्ने की कीमतें बढ़ाई

हिसार । दिवाली से पहले किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए हे रियाणा सरकार ने गन्ने की कीमतों में 14 रुपये का इजाफा किया है। इससे गन्ने के प्रति क्विंटल की कीमत में इजाफा हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चालू पेराई मौसम के लिए गन्ने की कीमत 14 रुपये बढ़ाकर 386 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। यह अभी 372 रुपये प्रति क्विंटल थी। इसकी घोषणा खट्टर ने सोशल मीडिया पर भी की है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि गन्ने की कीमतें बढ़ने से किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। खट्टर ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, मेरे गन्ना उत्पादक किसान भाइयों के लिए, मैं आज हरियाणा में गन्ने की प्रति क्विंटल दर 372 रुपये से बढ़ाकर 386 रुपये करने की घोषणा करता हूं। हमारे किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है कि यह देश में गन्ने का सबसे ऊंची दर होगी। पड़ोसी राज्य पंजाब में गन्ने की कीमत 380 रुपये प्रति क्विंटल है। खट्टर ने यह भी घोषणा की कि अगले साल यह दर बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल कर दी जाएगी। 386 रुपये प्रति क्विंटल की नई कीमत चालू पेराई सत्र से लागू होगी। इससे पहले जनवरी में खट्टर ने गन्ने की कीमत में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे फसल की दर बढ़कर 372 रुपये प्रति क्विंटल हो गई थी।

एचपीसीएल को जुलाई-सितंबर तिमाही में 5,827 करोड़ रुपये का मुनाफा

मुंबई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 5,826.96 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो कि पिछले वर्ष की समान तिमाही 2,476 करोड़ रुपये के भारी घाटे से उबरने में मददगार है। हालांकि, क्रमिक रूप से, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण एचपीसीएल का शुद्ध लाभ अप्रैल-जून तिमाही के 6,765.50 रुपये के लाभ से 14 प्रतिशत कम हो गया।एचपीसीएल ने अप्रैल-सितंबर 2023 के दौरान 12,592 करोड़ रुपये का अपना अब तक का सबसे अधिक अर्ध-वार्षिक समेकित शुद्ध लाभ कमाया है (पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 11,033 करोड़ रुपये के समेकित शुद्ध घाटे के मुकाबले)।इस अवधि के दौरान कंपनी का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ भी अब तक का सबसे अधिक 11,322 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान कंपनी का स्टैंडअलोन शुद्ध घाटा 12,369 करोड़ रुपये था। जुलाई-सितंबर 2023 की अवधि के लिए स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ 5,118 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 2,172 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। जुलाई-सितंबर 2023 की अवधि के लिए औसत जीआरएम (निर्यात शुल्क का सकल) 13.33 डॉलर प्रति बैरल (पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 8.41 डॉलर प्रति बैरल) था। अप्रैल-सितंबर 2023 की अवधि के लिए औसत जीआरएम (निर्यात शुल्क का सकल) 10.49 डॉलर प्रति बैरल (पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 12.62 डॉलर प्रति बैरल) था।एचपीसीएल रिफाइनरियों ने जुलाई-सितंबर 2023 (111.6 प्रतिशत पर परिचालन) के दौरान 5.75 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) के अपने उच्चतम तिमाही क्रूड को संसाधित किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान संसाधित 4.49 एमएमटी क्रूड से 28 प्रतिशत अधिक है। .

13.7प्रतिशत साइबर हमलों के साथ भारत सर्वाधिक लक्षित देश : रिपोर्ट

नई दिल्ली।

सभी साइबर हमलों में 13.7 प्रतिशत के साथ भारत सबसे अधिक लक्षित देश है, इसके बाद 9.6 प्रतिशत के साथ अमेरिका, 9.3 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत के साथ इंडोनेशिया और चीन हैं। सोमवार को जारी एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।साइबर सुरक्षा फर्म साइफिरमा के अनुसार, 2022 में भारत सबसे अधिक लक्षित देश था, क्योंकि सरकारी एजेंसियों पर हमले दोगुने से अधिक हो गए। 2022 की दूसरी छमाही में सरकारी एजेंसियों पर 2021 की समान अवधि की तुलना में 95 प्रतिशत अधिक साइबर हमले हुए। भारत में राज्य प्रायोजित साइबर हमलों की संख्या 2021 की तुलना में 2022 में 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई। रिपोर्ट के अनुसार, हेल्थकेयर हैकर्स द्वारा सबसे अधिक लक्षित क्षेत्र है,

इसके बाद शिक्षा, अनुसंधान, सरकार और सैन्य क्षेत्र हैं। साइफिरमा के सीईओ और संस्थापक कुमार रितेश ने कहा, विशे व मंच पर भारत की बढ़ती प्रमुखता और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अन्य बड़े देशों की तुलना में भारत का पक्ष लेने के दबाव, कम साइबरसेक परिपक्वता वाली एक युवा और तकनीक-प्रेमी आबादी ने महत्वपूर्ण संपत्तियों, सरकारी एजेंसियों के पीछे आने वाले हैकरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, रिपोर्ट से पता चला है कि 2022 में भारत में किसी संगठन पर प्रति सप्ताह औसतन 1,866 बार हमला किया गया। साइबर हमलों के सबसे आम प्रकार फ़िशिंग हमले, मैलवेयर हमले और रैंसमवेयर हमले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में लगभग 78 प्रतिशत भारतीय संगठनों ने रैंसमवेयर हमले का अनुभव किया, जिनमें से 80 प्रतिशत हमलों के परिणामस्वरूप डेटा एन्क्रिप्शन हुआ।

पांच राज्यों में चुनावों से पहले बाजार सतर्क

नई दिल्ली।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने मंगलवार को कहा कि बाजार में उच्च स्तर पर कुछ प्रतिरोध देखा गया है। कई राज्यों में चुनावों के चलते सावधानी बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि चीनी निर्यात में उम्मीद से अधिक गिरावट के कारण नकारात्मक वैश्विक संकेत मिले हैं, जो वैश्विक व्यापार में जारी मंदी को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और रूस द्वारा आपूर्ति में कटौती की अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है, जो भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत के लिए सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा, यह अमेरिकी बांड यील्ड में नरमी और पॉजिटिव अर्निंग सीजन के साथ, लॉन्ग टर्म रिटर्न का समर्थन करेगा। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर ने कहा कि निफ्टी 5.05 अंकों के मामूली नुकसान के साथ 19,406.70 पर बंद हुआ। सेक्टरों में, फार्मा 1.32 प्रतिशत की बढ़त के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला रहा, जबकि मुनाफावसूली के दबाव ने रियल्टी सेगमेंट को नीचे खींच लिया। आईटी और मेटल क्षेत्र में खास स्टॉक पर कार्रवाई देखी गई। मिड और स्मॉलकैप ने बढ़त बनाई और फ्रंटलाइन इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया।

इंडिगो अगले वर्ष बाली, मदीना के लिए उड़ानें शुरू करेगी: सीईओ

गुरुग्राम । विमानन कंपनी इंडिगो ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में बाली और मदीना के लिए उड़ानें संचो लित करने योजना बनाई है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स ने यह बात कही। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि एयरलाइन चालू वित्त वर्ष में 10 करोड़ यात्रियों को सफर कराने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सितंबर तिमाही में कंपनी ने 2.6 करोड़ यात्रियों को सेवाएं दीं और उसे 189 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। एल्बर्स ने कहा कि हम अपना अंतरराष्ट्रीय विस्तार जारी रखेंगे। इस समय एयरलाइन 100 अंतरराष्ट्रीय सहित लगभग 500 मार्गों पर संचालन करती है।

शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद

सेंसेक्स 825 , निफ्टी 264 अंक गिरा

मुम्बई ।

घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को मामूली गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आया है। इसके अलावा एशियाई बाजारों में आई गिरावट और वित्तीय व संपत्ति कंपनियों के शेयर में बिकवाली से भी बाजार पर दबाव आया। बाजार के 13 प्रमुख क्षेत्रों में से 9 में गिरावट रही। वित्तीय क्षेत्र में 0.5 फीसदी की गिरावट रही। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में से क्षेत्र 2.05 फीसदी तक बढ़ा है। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित, बीएसई सेंसेक्स 16.29 अंक करीब 0.03 फीसदी नीचे आकर 64,942.4 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 65 हजार से ऊपर जाने के बाद 64,638 अंक तक नीचे आया। वहीं इसी प्रकार पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी-50 भी 8.75 अंक तकरीबन 0.05 फीसदी नीचे आकर 19,403 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी की 30 कंपनियों के शेयर लाभ के साथ ही ऊपर आये जबकि 20 के शेयर नुकसान के साथ ही गिरावट पर बंद हुए। इस दौरान सेंसेक्स की कंपनियों में से सन फार्मा का शेयर सबसे ज्यादा 1.92 फीसदी

ऊपर आया। इसके अलावा एनटीपीसी, भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक के शेयर भी उछले जबकि बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टुब्रो और भारती एयरटेल के शेयर नीचे आये।

वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2.12 फीसदी नीचे आकर 83.37 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर फिसल गया। विदेशी निवेशकों ने गत दिवस 549.37 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। इससे पहले आज सुबह बाजार में सुस्ती देखी जा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी मिलेजुले कारोबार के साथ खुले हैं। सेंसेक्स हरे निशान में खुला है तो निफ्टी मामूली फिसलकर कारोबार कर रहा था। बैंक निफ्टी में 170 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है और ये 43500 के नीचे कारोबार पर है। बीएसई का सेंसेक्स 62.6 अंकों की मामूली तेजी के साथ 65,021 के स्तर पर खुला है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 8 अंक फिसलकर 19,404 के स्तर पर खुला है।

अमेरिका स्थित अहेड गुरुग्राम में खोल रहा ऑफिस, अगले 12 महीनों में करेगा 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति

नई दिल्ली।

क्लाउड, डेटा और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के लीडिंग प्रोवाइडर अहेड ने मंगलवार को गुरुग्राम में एक डेडिकेटेड सर्विस डिलीवरी ऑफिस खोलने की घोषणा की और कहा कि वह देश में अगले 12 महीनों में 1,000 से ज्यादा व्यक्तियों को नियुक्त करने की योजना बना रही है।यह अमेरिका के बाहर अहेड के उद्घाटन कार्यालय का प्रतीक है और इसकी वैश्विक विस्तार रणनीति के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में भारतीय बाजार के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

अहेड इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रवीण ग्रोवर ने एक बयान में कहा, अमेरिका के बाहर हमारे पहले डिलीवरी सेंटर की शुरूआत देश में इनोवेशन और डिजिटल विकास को गति देने के लिए तैयार है। हम अपनी सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने के लिए 1,000 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने की योजना पर काम करेंगे। कंपनी ने कहा कि नए ऑफिस के जरिए वह न केवल अपने क्लाइंट डिलीवरी क्षमताओं में तेजी ला रहे हैं, बल्कि खुद को लोकल कल्चर में इंटीग्रेटेड भी कर रहे हैं। अहेड के संस्थापक और सीईओ डैनियल एडमनी ने कहा, भारत की डिजिटल ग्रोथ स्टोरी विश्व स्तर पर सबसे रोमांचक

अवसरों में से एक है और हम इसका हिस्सा बनकर रोमांचित हैं। अपने पहले विदेशी डिलीवरी लोकेशन के जरिए, हमारा लक्ष्य अपने कस्टमर्स के लिए एक स्थायी और सकारात्मक प्रभाव डालना है।

अहेड क्लाउड, डिजिटल इंजीनियरिंग, डेटा और एनालिटिक्स, डेटा सेंटर आधुनिकीकरण, बिजनेस ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी और मैनेज सर्विस में एडवांस टेक्नोलॉजी सर्विस और सॉल्यूशन की एक विस्तृत रेंज प्रदान करता है।

विस्तार ने बोइंग और एयरबस उड़ानों में वाई-फाई सेवा शुरू की

मुंबई । एयरलाइन कंपनी विस्तार ने कहा कि उसने अपने बोइंग 787 और एयरबस ए321 नियो उड़ानों में वाई-फाई इंटरनेट सेववा की शुरुआत कर दी है। कंपनी ने कहा कि यह सेवा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर उसके लॉयल्टी कार्यक्रम और क्लब विस्तार सदस्यों के लिए होगी। कंपनी ने कहा कि इसके साथ ही विस्तार ऐसी सुविधा देने वाली पहली घरेलू एयरलाइन बन गई है। एयरलाइन ने कहा कि यह सुविधा क्लब विस्तार के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध है। क्लब विस्तार में शामिल होने के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी। विस्तार के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने कहा` कि इंटरनेट से जुड़े रहना आधुनिक जीवन का एक अनिवार्य पहलू है। हम चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर अपने लॉयल्टी कार्यक्रम और क्लब विस्तार सदस्यों को वाई-फाई की पेशकश करके प्रसन्न हैं।

मल्टी-क्लाउड एप्लिकेशन एफ5 ने की 120 कर्मचारियों की छंटनी

सैन फ्रांसिस्को/नई दिल्ली-

अमेरिका स्थित मल्टी-क्लाउड एप्लिकेशन सिक्योरिटी और डिलीवरी में वैश्विक अग्रणी कंपनी एफ5 ने कथित तौर पर 120 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। गीकवायर की एक रिपोर्ट के अनुसार, एफ5 छंटनी निवेश और संसाधनों को उन पहलों के साथ संरेखित करती है, जो हमारे कस्टमर्स के लिए हाइब्रिड और मल्टी-क्लाउड एप्लिकेशन सिक्योरिटी और डिलीवरी को आसान बनाने की हमारी रणनीति को तेज करती हैं। नौकरी में कटौती से कंपनी के 2 प्रतिशत से भी कम कार्यबल पर असर पड़ा है, जिसमें लगभग 6,400 लोग कार्यरत हैं। पिछले महीने के अंत में, सिएटल स्थित एफ5 ने अपनी चौथी तिमाही और 30 सितंबर को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा की। वित्तीय वर्ष 2023 का राजस्व एक साल पहले की अवधि से 4 प्रतिशत बढ़कर 2.8 बिलियन डॉलर हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2022 में 2.7 बिलियन डॉलर से अधिक है। वैश्विक सेवाओं का राजस्व एक साल पहले की अवधि से 7 प्रतिशत बढ़ा, जबकि उत्पाद राजस्व 1 प्रतिशत बढ़ा। एफ5 के अध्यक्ष और सीईओ फ्रेंकोइस लोको-डोनोउ ने कहा, हमारी चौथी तिमाही में, हमने 11 प्रतिशत सॉफ्टवेयर राजस्व वृद्धि, ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार और प्रति शेयर आय में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की।लोको-डोनोउ ने कहा, हम वित्तीय वर्ष 2024 में ऐसे माहौल में प्रवेश कर रहे हैं जो स्थिर होता दिख रहा है। वास्तव में, मांग के नजरिए से, पूरे वित्तीय वर्ष 2023 में सदस्यता नवीनीकरण ने अच्छा प्रदर्शन किया और हमने अपनी चौथी तिमाही में उद्यम ग्राहकों से उत्साहजनक संकेत देखे।वित्तीय वर्ष 2024 के लिए, एफ5 को राजस्व की उम्मीद है जो उसके वित्तीय वर्ष 2023 के राजस्व से कम-एकल-अंकीय प्रतिशत की गिरावट के बराबर है। इस साल मई में, एफ5 ने बेंगलुरु में अपना नया इंजीनियरिंग

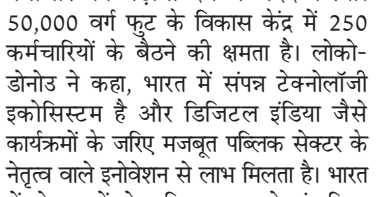

केंद्र खोला जो अनुसंधान, विकास और उत्पाद नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। 50,000 वर्ग फुट के विकास केंद्र में 250 कर्मचारियों के बैठने की क्षमता है। लोको-डोनोउ ने कहा, भारत में संपन्न टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिए मजबूत पब्लिक सेक्टर के नेतृत्व वाले इनोवेशन से लाभ मिलता है। भारत में दो दशकों से अधिक समय से संचालित, हैदराबाद में एफ5 का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास केंद्र अमेरिका और इजरायल में अपने अन्य वैश्विक इंजीनियरिंग केंद्रों के साथ मिलकर अपने समाधान पोर्टफोलियो को बढ़ाने के उद्देश्य से काम करता है।

बी2बी खर्च में बढ़ोतरी के मामले में भारतीय व्यवसाय विश्व में अग्रणी : अमेरिकन एक्सप्रेस सर्वे

नई दिल्ली।

अमेरिकन एक्सप्रेस के सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च (सीईबीआर) के सहयोग से हाल में कराए गए एक सर्वे से पता चला है कि भारतीय बिजनेस वैश्विक लीडर्स के रूप में उभर रहे हैं, जिसमें 72 प्रतिशत लोगों को 2023 में बी2बी खर्च में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो वैश्विक औसत 49 प्रतिशत से अधिक है। बी2बी खर्च में इस उछाल के पीछे प्रेरक शक्ति मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी निवेश है, उल्लेखनीय 88 प्रतिशत भारतीय व्यवसाय पहली छमाही की तुलना में 2023 की दूसरी छमाही में तकनीकी प्रगति के लिए अधिक धन आवंटित करने की योजना बना रहे हैं। यह कदम भुगतान की गति में सुधार, उत्पादकता बढ़ाने और अधिक डिजिटल उत्पादों के लिए ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के उनके लक्ष्यों के अनुरूप है। बिजनेस ट्रेवल फिर वापसी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 72 प्रतिशत भारतीय बिजनेस यात्रा, मनोरंजन और खर्चों पर खर्च बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। यह नेटवर्किंग, उद्योग अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और संभावित साझेदारियों की खोज पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है। इसके अलावा, 68 प्रतिशत भारतीय बिजनेस व्यवसाय और पेशेवर सेवाओं में अधिक निवेश करने का इरादा रखते हैं, जिनमें से एक अहम हिस्सा तकनीकी प्रगति का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए आईटी और प्रौद्योगिकी परामर्श सेवाओं पर अधिक खर्च की उम्मीद करता है। मनीष कपूर, उपाध्यक्ष और प्रमुख, ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज (जीसीएस), अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, भारत ने कहा, यह उल्लेखनीय है कि 84 प्रतिशत भारतीय व्यवसायों ने प्रभावशाली तरीके से अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान को आंशिक रूप से स्वचालित करने के लिए कदम उठाए हैं। 39 प्रतिशत अपनी भुगतान प्रक्रियाओं का पूर्ण स्वचालन प्राप्त कर रहे हैं। जैसे-जैसे व्यावसायिक परिदृश्य तेजी से प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है, स्मार्ट और अधिक कुशल भुगतान समाधान अपनाने की आवश्यकता सर्वोपरि हो जाती है।

उदाहरण के लिए, कॉरपोरेट कार्ड, विस्तारित भुगतान शर्तों, बी2बी व्यय पर रिवॉर्ड और निर्बाध भुगतान सुविधा की पेशकश के साथ, अपने खर्च कर सकते हैं, वे अधिक लाभप्रद और कुशल हैं, वे खर्च करने के साथ-साथ प्रभावी ढंग से कमाई भी करते हैं।

लेनोवो और ईपीओएस ने बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए हाई-क्वालिटी ऑडियो सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए मिलाया हाथ

नई दिल्ली।

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख लेनोवो और ऑडियो सॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी कंपनी ईपीओएस ने मंगलवार को बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए हाई-क्वालिटी ऑडियो सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट की घोषणा की। पार्टनरशिप के जरिए, ईपीओएस पीसी ऑडियो एक्सेसरीज के लिए लेनोवो का ग्लोबल ऑडियो पार्टनर होगा। ईपीओएस पोर्टफोलियो को लेनोवो के थर्ड-पार्टी ऑफरिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, जिससे कस्टमर्स को एक ही स्रोत से ऑडियो डिवाइस का व्यापक विकल्प मिलेगा।

एसवीपी वर्ल्डवाइड स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस सेगमेंट एंड कमर्शियल प्रोडक्ट सेंटर के लेनोवो आईडीजी एरिक यू ने बयान में कहा, ऑडियो टेक्नोलॉजी में लेनोवो और ईपीओएस की विशेषज्ञता के साथ, हम हाई-क्वालिटी ऑडियो सोल्यूशन प्रदान कर सकते हैं जो प्रोफेशनल यूजर्स की जरूरतों को पूरा करते हैं जो कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और ऑप्टीमल प्रोडक्टिविटी की मांग करते हैं। पार्टनरशिप के तहत, शुरूआती फेज में कॉन्फ्रेंस कॉल की हाइब्रिड वर्ल्ड को बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल्स यूजर्स के लिए डिजाइन किए गए चयनित हेडसेट जारी करना शामिल होगा। कंपनी ने कहा कि लेनोवो ईपीओएसको-ब्रांडेड हेडसेट में से दो अब भी उपलब्ध हैं, जो टीम्स और जूम के लिए प्रमाणित हैं, और अन्य यूसी ऐप्लिकेशन के लिए अनुकूलित हैं और ईपीओएस की सिग्नेचर साउंड क्वालिटी और कंफर्ट फीचर देते हैं। ईपीओएस के अध्यक्ष जेप्पे डालबर्ग-लार्सन ने कहा, लेनोवो के साथ इस उद्यम को शुरू करने से हमें इस प्रतिबद्धता को जारी रखने, अपनी ऑफरिंग का विस्तार करने और कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन एक्सपीरियंस के लिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मैं हमारी पार्टनरशिप के इस नए चैप्टर को लेकर बहुत उत्सुक हूं।

एलन मस्क की टेस्ला जनवरी 2024 तक भारत आ सकती है : रिपोर्ट

नई दिल्ली।

एलन मस्क द्वारा संचालित टेस्ला जल्द ही भारतीय सड़कों पर दौड़ सकती है। केंद्र सरकार देश में जनवरी 2024 तक इसके प्रवेश के लिए संबंधित विभागों से सभी आवश्यक मंजूरी प्रदान करने की प्रक्रिया तेज कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने टेस्ला के निवेश प्रस्ताव सहित देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण के आगामी चरण की समीक्षा के लिए सोमवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। जून में अमेरिका की यात्रा के दौरान मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक बैठक हुई थी। इसके बाद, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, भारी उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में टेस्ला की योजनाओं के बारे में चर्चा में लगे हुए हैं। सितंबर में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि टेस्ला भारत में बैटरी स्टोरेज के लिए एक फैक्ट्री बनाने की योजना बना रही है और उसने सरकार को इसके लिए एक प्रस्ताव भी भेजा है। इलेक्ट्रिक कार निर्माता ने हाल की बैठकों के दौरान अपने पावरवॉल के साथ देश की बैटरी भंडारण क्षमता का समर्थन करने का प्रस्ताव रखा।मस्क भारत में टेस्ला आपूर्ति प्रणाली बनाने का भी लक्ष्य बना रहे हैं।केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि ईवी प्रमुख इस साल भारत से 1.9 बिलियन डॉलर तक के ऑटोमोबाइल पार्ट्स खरीदने की योजना बना रही है। मंत्री ने कहा कि पिछले साल टेस्ला ने पहले ही भारत से 1

अरब डॉलर के कंपोनेंट खरीदे थे और इस साल उनका लक्ष्य 1.7-1.9 अरब डॉलर का है।

विश्वकप में आज नीदरलैंड को हराने के इरादे से उतरेगी इंग्लैंड

पुणे (एजेंसी)। एकदिवसीय विश्वकप में बुधवार को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी गत विजेता इंग्लैंड का मुकाबला डच टीम नीदरलैंड से होगा। इस मैच में जीत के लिए इंग्लैंड टीम पूरी ताकत लगा देगी जिससे कि एक बार फिर जीत की लय हासिल की जा सके। इंग्लैंड टीम विश्वकप में एक ही मैच जीतने के कारण अंक तालिका में अंतिम स्थान पर है। इससे उसके लिए चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालीफाई करना भी कठिन हो गया है।

इंग्लैंड की टीम का पलड़ा भारी तो है पर ये मैच उसके लिए आसान नहीं है क्योंकि उसके बल्लेबाज और गेंदबाज फार्म में नहीं हैं। वहीं नीदरलैंड ने विश्वकप में उम्मीद से बेहतर खेल दिखाया है। ऐसे में वह भी इंग्लैंड को कड़ी टक्कर देगी। उसने विश्वकप में दक्षिण अफ्रीका को भी उलटफेर का शिकार बनाकर सबको हैरान की दिया था।

इस मैच में इंग्लैंड की टीम लगातार हार के दौर से बाहर निकलने के लिए उतरेगी। नहीं नीदरलैंड भी दक्षिण अफ्रीका की तरह इंग्लैंड को हराकर सबको हैरान करना चाहेगी।

इंग्लैंड की टीम का मनोबल इस विश्वकप में गिरा हुआ है। ऐसे में उसके बल्लेबाज और गेंदबाज बेहतर प्रदर्शन कर अपना मनोबल बढ़ाना चाहेंगे। यहां की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल है जिससे यहां पर बड़ा स्कोर बनने की संभावना है। ऐसे में गेंदबाजों के लिए बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना कठिन

होगा। स्पिनर हालांकि इस पिच पर सहायता हासिल कर सकते हैं।

वहीं मौसम विभाग के अनुसार यहां बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है।

दोनो ही टीमें इस प्रकार हैं

इंग्लैंडः जोस बटलर(कप्तान), जॉनी बेयरेस्टो, डेविड मलान, जो रूट, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, मोईन अली, डेविड विली, मार्क वुड, आदिल रशीद, क्रिस वोक्स

नीदरलैंडः स्कॉट एडवर्ड्स(कप्तान), मैक्स ओ'डोड, वेस्ले बेरेसी, कॉलिन एकरमैन, बास डी लीडे, साइब्रांड एंगेलब्रेक्ट, साकिब जुल्फिक्कार, लोगान वान बीक, रुलोफ वानडेर मर्व, आर्यन दत्त, पॉल वान मीकेरन।

अफगानिस्तान टीम ने रचा इतिहास, वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए किया क्वॉलिफाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान टीम मुंबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला खेल रही है। वहीं अभी तक टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जहां उसने अपने पिछले तीन मैचों में जीत हासिल की है। इसके साथ ही अफगानिस्तान टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया है। अफगान टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हिस्सा होगी।

बता दें कि, सोमवार को बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच दिल्ली में खेले गए मुकाबले में श्रीलंकाई टीम की 3 विकेट से हार के बाद अफगानिस्तान टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। अफगान टीम ने इस वर्ल्ड कप में 7 मैच खेले है और 4 में जीत हासिल की है। अफगानिस्तान ने कई बड़ी टीमों को मात दिया, जिसमें इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और नीदरलैंड्स शामिल है।

बता दें कि, अफगानिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है। उसे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए सभी मैच जीतने होंगे। फिलहाल उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले के बाद साउथ अफ्रीका से भिड़ना है।

विश्वकप में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकार्ड बना

नई दिल्ली (एजेंसी)। श्रीलंकाई बल्लेबाज कुशल डेडिंस के बांग्लादेश के खिलाफ मैच में छक्का लगाते ही 2023 विश्वकप में सबसे अधिक 464 छक्के लग गये हैं। इससे पहले सबसे अधिक छक्कों का रिकार्ड 2015 विश्वकप में बना था। तब 463 छक्के लगे थे। वहीं इस विश्वकप के 37 मैचों में ही अब तक इतने छक?के लग गये हैं। वहीं आज हुए 38 वें मैच में एक छक्का लगाते ही नया रिकार्ड बन गया। .इस विश्कप से पहले दो विश्वकप ही ऐसे रहे हैं जिसमें अब तक 400 से अधिक छक्के लगे हैं। साल 2015 के विश्वकप में प्रशंसकों को 463 छक्के देखने को मिले थे। इन दो वर्ल?डकप के अलावा 2007 और 2019 के इस टूर्नामेंट में छक्कों की संख्या 350 से अधिक थी। वहीं साल 2007 के वर्ल्डकप में 373 और 2019 के विश्वकप में 357 छक?के ही लगे थे।

सबसे पहले हुए 1975 और 1979 विश्वकप में सबसे कम 28 छक्के लगे थे जबकि 1983 में इनकी तादाद बढ़कर 1983 पहुंच गयी थी। 1987 में 126 छक्के और 1992 में 93 छक?के लगे जबकि 1996 में 148 छक?के लगे। वहीं 1999 विश्वकप में 153 छक्के और 2003 में 266 छक्के लगे। 2007 में इनकी संख्या बढ़ 373 तक पहुंच गयी। साल 2011 में 258 छक्के

वहीं 2015 में 463 छक?के लगे। 2019 में इनकी संख्या घटकर 357 छक्के तक पहुंच गयी। इस विश्वकप में सबसे अधिक छक्के भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने लगाये हैं। रोहित ने अब तक 8 मैचों में अब तक 22 छक्के लगाये हैं। वहीं सात मैचों में 20 छक्कों के साथ ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर दूसरे और 18-18 छक्कों के साथ पाकिस्तान के फखर जमां)और दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक इस सूची में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं।

वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रॉफी लेकर निकलेंगे लीजेंड्स लीग क्रिकेटर: अश्विनी वैष्णव

-भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी करके गर्व का अनुभव कर रहे-रवि शास्त्री

नई दिल्ली (एजेंसी)। लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ एक साझा राष्ट्रीय अभियान की घोषणा की है। आठ नवंबर बुधवार से शुरु हो रहे इस अभियान में लीजेंड्स लीग में भाग लेने वाले क्रिकेटर अब वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रॉफी के साथ यात्रा करेंगें। इस अभियान के दौरान ये ट्रॉफी वंदे भारत एक्सप्रेस से कई राज्यों की यात्रा करेगी। ट्रॉफी पूरे देश में 17 विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यात्रा करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसको लेकर उत्साहित हैं उन्होंने कहा, हम लीजेंड्स लीग क्रिकेट और वंदे भारत में दिग्गज खिलाड़ियों

का स्वागत करते हैं। देश भर में खेलों को बढ़ावा देने की इस अविश्वसनीय यात्रा के लिए हम तैयार हैं।

वहीं लीजेंड्स लीग क्रिकेट के कमिश्नर रवि शास्त्री ने कहा, हमें भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी करने और खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देने पर गर्व का अनुभव हो रहा है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट में खेल हर दिन बड़ा होता जा रहा है। मैं कहूंगा कि इस सीज़न में लीजेंड्स लीग क्रिकेट धमाल मचाने वाले हैं। यह अभियान 8 नवंबर को नई दिल्ली से शुरू हो रहा है और 16-रूट की इस यात्रा में से यह पहली यात्रा होगी। लीजेंड्स लीग क्रिकेट के सीईओ रमन रहेजा ने कहा, जैसा कि हमने भारतीय रेलवे के साथ इस अनूठे सहयोग को हरी झंडी दिखाई है, लीजेंड्स लीग क्रिकेट प्रशंसकों को सर्वोत्तम अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह देश के हर कोने में खेल की संस्कृति को बढ़ावा देने की एक नई पहल है। गेल, श्रीसंत और वॉटसन जैसे शीर्ष दिग्गज एलएलसी ट्रॉफी के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस में देश भर के दौरे पर निकलेंगे। इस अभियान में गौतम गंभीर, सुरेश रैना, इरफान पठान, क्रिस गेल, केविन पीटरसन, एस श्रीसंत, पार्थिव पटेल, शेन वॉटसन, प्रवीण कुमार, झूलन गोस्वामी जैसे क्रिकेट के दिग्गजों को शामिल किया गया है।

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड बहाल, बोर्ड अध्यक्ष शम्मी ने दी थी अदालत में चुनौती

कोलंबो (एजेंसी)। श्रीलंका के खेल मंत्री रोशन रणसिंघे द्वारा बर्खास्त किए गए देश के क्रिकेट बोर्ड को वहां की अदालत ने मंगलवार को बहाल कर दिया है। अदालत ने बोर्ड अध्यक्ष शम्मी सिल्वा की खेल मंत्री रणसिंघे द्वारा क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त किए जाने के कदम को अदालत में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।

मीडिया रिपोर्ट'के अनुसार श्रीलंका कोर्ट ऑफ अपील ने देश के क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त करने के खेल मंत्री के फैसले को रद्द करते हुए सुनवाई पूरी होने तक निष्कासित अधिकारियों को बहाल कर दिया। उल्लेखनीय है कि विश्व कप में भारत से शर्मनाक हार के बाद सोमवार को श्रीलंका के खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने देश के क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था।

गौर हो कि खेल मंत्रालय ने बोर्ड को बर्खास्त करते हुए एक विज्ञप्ति में कहा था कि समिति की नियुक्ति रणसिंघे द्वारा 1973 के खेल कानून संख्या 25 की शक्तियों के तहत की गई है। समिति में तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हैं, जिनमें से दो महिलाएं हैं और पूर्व एसएलसी अध्यक्ष उपाली धर्मदासा भी हैं। इससे रणतुंगा की वापसी हुई जिन्होंने 2008 में श्रीलंकाई क्रिकेट के मामलों के शीर्ष पर इसी तरह की अंतरिम समिति का नेतृत्व भी किया था। रणसिंघे द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय खेल परिषद के प्रमुख रणतुंगा सिल्वा प्रशासन पर सवाल उठाते रहे हैं। सिल्वा को मई में उनके लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एसएलसी प्रमुख के रूप में चुना गया था जो 2025 तक चलना था।

न्यूजीलैंड-श्रीलंका मैच में बारिश हुई तो पाक के पास रहेगा सेमीफाइनल में पहुंचने का अवसर

नई दिल्ली । विश्वकप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें दावेदारी में बनी हुई हैं। न्यूजीलैंड की टीम पर अंक तालिका में पाक से आगे है। पाक टीम अब तक खेले 8 में से 4 ही मुकाबले जीत पायी है। ऐसे में पाक टीम 8 अंकों के साथ ही अंक तालिका में 5वें नंबर पर है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम के भी 8 मैच में 8 अंक हैं पर नेट रनरेट के कारण कीवी टीम अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। ऐसे में दोनो ही टीमों के लिए अपने-अपने अंतिम मैच अहम रहेंगे। न्यूजीलैंड को अपना अंतिम मैच 9 नवंबर को बेंगलुरु में श्रीलंका से खेलना है। वहीं पाक टीम 11 नवंबर को इंग्लैंड से खेलेगी। वहीं कहा जा रहा है कि 9 नवंबर को बेंगलुरु में बारिश की काफी संभावना है। ऐसे में अगर मैच रद्द होता है, तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड दोनो ही टीमों को एक-एक अंक मिलेंगे। इस कारण कीवी टीम के कुल अंक 9 हो जाएंगे। वहीं पाक की टीम यदि इंग्लैंड को हरा देती है, तो उसके 10 अंक हो जाएंगे और वह कीवी टीम से आगे निकल जाएगी। वहीं अफगानिस्तान के भी 7 मैच में 8 अंक हैं पर उसके बचे 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से होने हैं। ऐसे में उसकी जीत की संभावनाएं कम हैं। ऐसे में पाक टीम के लिए सेमीफाइनल की राह बन जाएगी।

रोहित ने दी टीम को अतिआत्मविश्वास से बचने की सलाह

कोलकाता । भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि आने वाले मुकाबलों के लिए टीम को अतिआत्मविश्वास से बचना होगा। रोहित के अनुसार अभी तक टीम को जबरदस्त सफलता मिली है और उसने दक्षिण अफ्रीका जैसे टीम को भी 243 रन के बड़े अंतर से हराया है। रोहित ने कहा कि खिलाड़ियों को अतिआत्मविश्वास से बचना होगा क्योंकि आने वाले मुकाबले और कठिन होंगे। रोहित शर्मा ने विश्वकप मे आठवीं जीत दर्ज करने पर कहा कि टीम को अभी कुछ और मैच खेलने हैं और उसे अतिआत्मविश्वास से बचना होगा। उन्होंने कहा कि हम अभी ड्रेसिंग रूम में इस बारे में ही बात कर रहे थे। हमें अतिआत्मविश्वास से बचते हुए अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलना होगा। रोहित ने कहा कि टीम ने पिछले 3 मैचों में बेहद ही शानदार खेल दिखाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 मैचों के प्रदर्शन को देखें तो हम स्थिति के अनुरूप ढलने के मामले में शानदार रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हम दबाव में थे, पिछले मैच में भी हमने पहले ओवर में एक विकेट खो दिए थे, लेकिन अच्छा स्कोर बनाया और तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। रोहित ने इस मुकाबले में वनडे में 49वां शतक लगाने वाले विराट कोहली के साथ शानदार साझेदारी करने वाले श्रेयस अय्यर की तारीफ की। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 134 रन जोड़े।

श्रेयस सबसे बेहतर तरीके से स्पिन खेलते हैं : कैफ

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा है कि श्रेयस अय्यर स्पिन को काफी अच्छे तरीके से खेलते हैं। श्रेयस ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्वकप मुकाबले में शानदार अर्धशतक लगाया था। अय्यर ने इस मुकाबले में 77 रनों की पारी खेली थी। अय्यर की इस शानदार पारी को देखकर कैफ बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है कि श्रेयस से बेहतर स्पिन कोई अन्य भारतीय खिलाड़ी नहीं खेल सकता है. कैफ ने कहा, श्रेयस स्पिन को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। मैंने आईपीएल में उनके साथ काम किया है। मेरा मानना है कि टीम का कोई भी खिलाड़ी उनसे बेहतर स्पिन नहीं खेल सकता है क्योंकि वह एक ओर दो रन लेते रहते हैं। साथ ही छक्के भी मारते हैं। कितनी भी अच्छी गेंदबाजी हो उनपर प्रभाव नहीं पड़ता। अय्यर अपनी तरफ से रन निकालते रहते हैं। अय्यर ने विश्व कप की अपनी पहली 6 पारियों में केवल एक अर्धशतक बनाने के बाद, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ वापसी की। इन दोनों ही टीमों के खिलाफ उन्होंने अर्धशतक लगाये। अय्यर ने श्रीलंका के खिलाफ 56 गेंदों में 82 रन और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 87 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली।

गांगुली भी बचे थे टाइमआउट से, स्मिथ ने नहीं की थी अपील

नई दिल्ली । एकदिवसीय विश्वकप में श्रीलंकाई बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइमआउट होने वाले पहले बल्लेबाज हैं। बंग्लादेश के

खिलाफ मुकाबले में वह शकिब अल हसन की अपील के कारण आउट हुए। इससे पहले एकबार भारतीय टीम के बल्लेबाज सौरव गांगुली भी टाइमआउट होते पर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ग्रीम स्मिथ ने उनके आउट होने की अपील नहीं की जबकि स्मिथ को पता था कि वह तय समय से देरी से आये हैं। यह साल 2007 का मामला है। उस समय भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में टेस्ट मैच खेल रही थी। तब भारत ने तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में के रूप में दो विकेट शुरुआत में ही खो दिये। इसके बाद बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को उतरना था पर किसी कारण वह वह उतर नहीं पाये। इसके बाद बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को आना था पर वह नहा रहे थे। ऐसे में गांगुली को अचानक ही उतरना पड़ा। वह जल्दी से ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और तैयार होकर मैदान पर आए पर उन्हें उतरने में तीन मिनट से ज्यादा का समय लग गया। इस कड़ी में करीब 6 मिनट से ज्यादा का समय लग गया था। तब स्मिथ ने खेल भावना का ध्यान रखते हुए गांगुली को आउट देने की अपील नहीं की।

विश्व कप में भारतीय प्रशंसकों के समर्थन से प्रेरित हो रही अफगानिस्तान की टीम : कप्तान शाहिदी

मुंबई (एजेंसी)। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा कि अफगानिस्तान की टीम विश्व कप के दौरान भारतीय प्रशंसकों के समर्थन से काफी हद तक प्रेरित हुई है और मानसिकता में बदलाव से उनकी टीम पिछले चरण की तुलना में इस टूर्नामेंट में ज्यादा जीत हासिल करने में सफल रही है। अफगानिस्तान लगातार तीन मैच जीतकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाने का लक्ष्य बनाए है जिससे टीम लीग चरण के अंतिम दो मैच जीतने की कोशिश करेगी।

आस्ट्रेलिया से भिड़ेगी शाहिदी ने मैच पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा, 'हम जैसा यहां खेल दिखा रहे हैं, स्वदेश में सभी इसे पसंद कर रहे हैं। देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमारी उपलब्धियों से बहुत खुश हैं।' उन्होंने कहा, 'भारतीय लोगों ने हमारा पूरे टूर्नामेंट में समर्थन किया है। वे प्रत्येक मैच में स्टेडियम में आ रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। इससे हमें प्रेरणा मिल रही है।'

शाहिदी ने कहा कि मैदान के बाहर भी भारतीय प्रशंसक पूरा समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'साथ ही

मैदान के बाहर जब वे हमें पहचानते हैं कि हम अफगानिस्तान टीम के खिलाड़ी हैं तो वे हमें बहुत सम्मान और प्यार देते हैं।' उन्होंने कहा, 'इनमें से एक व्यक्ति जो एक टैक्सी ड्राइवर था, मुझे बिना पैसे ही मेरे गंतव्य तक ले गया। भारत में लोग हमें इसी तरह प्यार दे रहे हैं। हम इसके आभारी हैं।'

शाहिदी ने यह भी कहा कि अच्छे प्रदर्शन के लिए टीम की मानसिकता में बदलाव भी जरूरी था। उन्होंने कहा, 'विश्व कप में हमारा पिछला प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था, हमने सिर्फ एक ही मैच जीता था। लेकिन इस विश्व कप में, हमें विश्वास था कि हम बेहतर कर सकते हैं।' अफगानिस्तान के कप्तान ने कहा, 'पहले अन्य टीमों और हमारे बीच जो अंतर था, मुझे लगता है कि अब हम उनके बराबर हैं जो शीर्ष स्तर की हैं। हम शायद अब भी सीख रहे हैं, लेकिन प्रतिभा की बात करें तो हम अच्छी टीम हैं।'

उन्होंने कहा, 'हमारी टीम में काफी प्रतिभा है और हमने जो कड़ी मेहनत की है, उसे देखते हुए हमें विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम यह हासिल कर सकते हैं।' शाहिदी ने कहा, 'भरोसा, कड़ी मेहनत और प्रतिभा ये तीन चीजें हैं जो हमारी टीम में है। शुरूआत से हमें विश्वास था लेकिन इसके लिए हमें जीत हासिल करनी होगी। जब हम इंग्लैंड के खिलाफ जीते तो यह भरोसा और बढ़ गया और इसके बाद पाकिस्तान को हराकर इसमें और इजाफा हुआ।' उन्होंने कहा, 'हम बस आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रत्येक मैच में बतौर टीम सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश कर रहे हैं।'

एफआईएच ने पेरिस ओलंपिक क्वालीफायर के लिए घोषित किया पूल

लुसाने । अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ (एफआईएच) ने 2024 पेरिस ओलंपिक क्वालीफायर के लिए पूल की घोषणा कर दी है। 13 से 24 जनवरी के बीच रांची में होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर में भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और चेक गणराज्य से होगा। आठ टीमों की इस प्रतियोगिता में शीर्ष 3 में रहने वाली टीमें ही पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए प्रवेश हासिल करेंगी। अब तक मेजबान फ्रांस के अलावा, पांच पुरुष और महिला टीमों ने ही कॉन्टिनेंटल चैंपियंस के रूप में पेरिस ओलंपिक ओलंपिक 2024 के लिए सीधे प्रवेश हासिल किया है। 16 पुरुष-महिला टीमों ने एक साथ एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर 2024 में अपना स्थान पक्का कर लिया है, इसलिए, इन क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के लिए पूल अब सामने आ गए हैं। प्रति जेंडर 16 टीमों को दो समूहों में बांटा गया है। जिसमें आठ टीमें प्रत्येक स्थान पर यात्रा करेंगी। पुरुषों के क्वालीफायर के लिए मस्कट, ओमान और वालेंसिया, स्पेन, और महिलाओं के लिए रांची, भारत और वालेंसिया, स्पेन वेन्यू होगा। मस्कट, ओमान में प्रतिस्पर्धा करने वाली आठ पुरुष टीमें ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, मलेशिया, पाकिस्तान, कनाडा, चिली और चीन हैं। वालेंसिया, स्पेन में प्रतिस्पर्धा करने वाली आठ पुरुष टीमें बेल्जियम, स्पेन, कोरिया, आयरलैंड, जापान, ऑस्ट्रिया, मिस्र और यूक्रेन हैं। वेलेंसिया, स्पेन में प्रतिस्पर्धा करने वाली आठ महिला टीमें बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, दक्षिण कोरिया, आयरलैंड, कनाडा, मलेशिया और यूक्रेन हैं।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर पहली बार पंजाब का कब्जा, अर्शदीप सिंह ने पलटी बाजी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पंजाब ने बडौदा को हराकर पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की है। मंदीप सिंह की अगुवाई में पंजाब ने बड़ौदा को 20 रनों से मात दी। इससे पहले पंजाब चार बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन कभी टाइटल अपने नाम नहीं किया था। इस बार ये कसर भी पंजाब ने पूरी कर दी।

इस मैच में दोनों टीमों ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया और कुल 426 रन बने। वहीं पंजाब की जीत के हीरो अनमोलप्रीत सिंह और अर्शदीप सिंह रहे। अनमोलप्रीत ने पहली पारी में शतक जड़कर 113 रन बनाए। वहीं अर्शदीप ने अपने 4 ओवर में मात्र 23 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। अर्शदीप ने 19वें ओवर में मैच को पलट दिया। हालांकि, अनमोलप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अनमोलप्रीत सिंह के शतक की बदौलत 224 का लक्ष्य दिया। जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने वाली बड़ौदा ने 18 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 191 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि बड़ौदा की टीम इस मैच को आसानी से जीत जाएगी। क्रुणाल पांड्या 45 तो विष्णु सोलंकी 7 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे थे। इस दौरान विष्णु ने 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 24 रन बटोरे थे।

चोटिल होने के कारण शाकिब विश्वकप से बाहर हुए

नई दिल्ली । बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान शाकिब अल हसन चोटिल होने के कारण एकदिवसीय विश्व कप के बचे हुए मैचों से बाहर हो गये हैं। शाकिब को श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी करते समय चोट लगी थी। मैच के बाद हुई जांच में तर्जनी में फ्रैक्चर निकला है। इससे वह पुणे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश के इस टूर्नामेंट के अंतिम मैच से बाहर हो गए हैं। वहीं राष्ट्रीय टीम के फिजियो बायजेदुल इस्लाम खान ने कहा, शाकिब को उनकी पारी की शुरुआत में बाईं तर्जनी पर चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने सहायक टेपिंग और दर्द निवारक दवाओं के साथ बल्लेबाजी करना जारी रखा। वहीं जांच में उनके फ्रैक्चर का पता चला है। इस चोट से उबरने के लिए उन्हें तीन से चार सप्ताह का समय लगेगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

मास्टर स्तर पर रोजगार से सीधे-सीधे रिश्ता जोड़ने में जिन कोर्स ने अपनी पहचान बनाई है, उनमें एमआईबी भी एक है. एमआईबी का मतलब है मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस. करीब 15 साल पहले शुरू किया गया यह कोर्स दिल्ली विश्वविद्यालय में खासा लोकप्रिय हो रहा है.

विश्व बाजार में नेतृत्व का हुनर सिखाए

एमआईबी

मास्टर स्तर पर जिन छात्रों को रोजगार की जरूरत होती है वे इस कोर्स में दाखिले का दरवाजा खटखटाते हैं. यह कोर्स छात्रों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में कॉरपोरेट जगत से रिश्ते बनाने का हुनर सिखाता है. इसके जरिए छात्रों में न सिर्फ ग्लोबल बिजनेस की गति को पहचानने की क्षमता ही नहीं बल्कि उसकी समझ, विश्लेषण और कम्युनिकेशन स्किल भी पैदा किया जाता है. इसके लिए लेक्चर, ट्यूटोरियल, केस स्टडीज, सेमिनार, बिजनेस गेम्स और अन्य आधुनिक तरीकों का सहारा लिया जाता है. इसके बाद कैट के स्कोर के आधार पर छात्रों को दाखिले की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा.

कोर्स प्रोफाइल

दो साल के इस कोर्स में चार सेमेस्टरों में छात्रों को बिजनेस मार्केटिंग स्किल, वैश्विक बिजनेस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू के साथ ही अन्य बातों के बारे में बताया जाता है. विश्व बाजार में चल रही प्रतिस्पर्धा, उससे निपटने की रणनीति, मानव संसाधन के बेहतर उपयोग, उसके लिए नवीनतम ज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी दी जाती है.

एक कुशल प्रबंधक के लिए क्या-क्या जरूरी हैं, बिजनेस लीडर बनने के लिए किन-किन गुणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी जानकारी दी जाती है. सिर्फ थ्योरी स्तर पर ही नहीं, इसके लिए उसे केस स्टडीज, सेमिनार, पेपर प्रजेन्टेशन और कार्यशाला का भी काम करना होता है. समूह के बीच काम करने और कंपनी के सामने बाजार की विभिन्न चुनौतियों से निपटने के तत्वों के बारे में भी बताया जाता है. निर्णय लेने की क्षमता की परख की जाती है. उसके लिए आवश्यक हुनर से भी लैस किया जाता है. यही नहीं, कोर्स के अंदर बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण मिले, इसके लिए छात्र-शिक्षक का अनुपात 13.1 रखा गया है. केस स्टडीज के तहत प्रतिभागी को एक मैनेजर के रूप में काम करना होता है. वह अपने आइडिया और समस्याएं तथा समकालीन मामलों को भी सामने रखता है.

क्या कहते हैं छात्र

एमआईबी के पूर्व छात्र रूपेश गांगुली इसे रोजगार के लिहाज से मैनेजमेंट प्रोग्राम सरीखा मानते हैं. गांगुली ने बताया कि रामजस कॉलेज से बीएससी करने के बाद जेएनयू एमएससी इनफॉग्रेटिक्स साइंस में दाखिला लिया. वहां से कोर्स करने के बाद रोजगार को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी की और प्रवेश परीक्षा में सफल हुआ. यह कोर्स सभी विषय के छात्रों को अवसर दिलाने में कामयाब है. यह सभी वर्ग और पृष्ठभूमि के छात्रों को आगे आने और दाखिला पाने का मौका देता है. यह अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम वाले छात्रों के सपने को भी साकार करता है. इसकी फीस भी मैनेजमेंट प्रोग्राम से काफी कम है. फीस के लिए बैंक लोन भी मुहैया कराते हैं. प्लेसमेंट छात्रों के लिए अक्टूबर के मध्य में बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ एक प्लेसमेंट का कार्य भी आयोजित किया जाता है. इनमें विभिन्न निजी कंपनियां आती हैं. प्लेसमेंट के लिए अल्यूमनाई की विशेष भागीदारी होती है.

दंत चिकित्सा

कमाई का सदाबहार क्षेत्र

सुंदर और स्वस्थ दिखने की प्रतिस्पर्धा में लोग आज सुंदर चेहरे के साथ-साथ चमकदार दांत भी चाहते हैं. मेडिकल क्षेत्र में रुचि लेने वाले युवाओं के लिए आज यह बेहतरीन करियर विकल्प है.

हमारे देश में अधिकतर लोग दांतों की बीमारियों से त्रस्त हैं. लोगों को अपने दांतों और मसूढ़ों को स्वस्थ रखने के लिए जिस अनुपात में चिकित्सकों की जरूरत है, वे हैं नहीं! आज भी दंत चिकित्सक बड़े शहरों और नगरों में ही मुख्य तौर पर उपलब्ध हैं. ऐसे में, यदि डेंटिस्ट बनकर अपना करियर संवारा जाए तो यह बेहतर विकल्प हो सकता है.

योग्यता - डेंटिस्ट बनने के लिए फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायोलॉजी विषय के साथ कम से कम 50 फीसद अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है. इसके बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता है. टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के 180 प्रश्न होते हैं. ये प्रश्न बायोलॉजी, जूलोजी, फिजिक्स और केमेस्ट्री से होते हैं.

इस परीक्षा में सफल होने के बाद ही उम्मीदवार को डेंटल कॉलेज में चार वर्षीय ऑल बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) में दाखिले का मौका मिलता है. यह कोर्स और प्रवेश परीक्षा डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है. इसके अलावा, राज्य स्तर पर भी परीक्षाओं के माध्यम से बीडीएस में प्रवेश पाया जा सकता है. डिग्री हासिल करने के बाद पांचवें साल में एक साल की इंटर्नशिप होती है. यह कोर्स का अनिवार्य हिस्सा है.

स्पेशलाइजेशन - बीडीएस कोर्स करने के बाद स्पेशलाइजेशन और गहन चिकित्सा का ज्ञान हासिल करने के लिए एमडीएस में भी प्रवेश जरूरी है. मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी में भी दाखिला प्रवेश परीक्षा के जरिए मिलता है. एमडीएस में स्पेशलाइजेशन विभिन्न तरह के हैं. इनमें इंडोडांटिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी, ओरल सर्जरी, ऑर्थोडोनटिक्स, पेडोडॉंटिक्स, पेरिडोंटिक्स एवं प्रोस्थोडोंटिक्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं. इनमें से किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी होती है. दंत चिकित्सा में विशेषज्ञ बनने के लिए इससे जुड़े प्रैक्टिस प्रोग्राम और देश-दुनिया में हो रहे नए प्रयोग, अनुसंधान और इलाजों की भी जानकारी रखनी होती है. डिग्री हासिल करने के बाद कई तरह के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी किया जा सकता है, जिससे दंत चिकित्सा के बारे में जानकारी अपडेट की जा सके.

फीस - सरकारी डेंटल कॉलेजों में बीडीएस कोर्स करने की फीस करीब एक लाख रुपये है लेकिन परेशानी की बात यह है कि देश में डेंटल कॉलेजों की संख्या काफी कम है. निजी कॉलेजों में चार साल की फीस 10 लाख रुपये से ऊपर है. एमडीएस कोर्स की फीस भी सरकारी में काफी कम है लेकिन निजी कॉलेजों में विभिन्न स्पेशलाइज्ड विभाग की अलग-अलग है. यह 25 लाख रुपये से ऊपर जाती है. गरीब वर्ग के जो छात्र मेरिट में आते हैं, उनके लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्कॉलरशिप की व्यवस्था है.

अवसर - वर्तमान में देश में डेंटल सर्जन की सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में काफी मांग है. आज पूरे देश में निजी अस्पतालों का जाल बिछ चुका है. इनमें बेहतर पैकेज और सुविधा के साथ दंत चिकित्सकों को नियुक्त किया जा रहा है. इसी तरह, निजी नर्सिंग होम और सरकार के बड़े डिस्पेंसरी में भी दंत चिकित्सक नियुक्त किये जा रहे हैं. सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों के अलावा रेलवे और रक्षा क्षेत्रों द्वारा संचालित अस्पतालों में डेंटिस्ट की नियुक्तियां करती हैं. टूथ पेस्ट बनाने और मसूढ़ों की देखरेख करने वाली कंपनियां अपने यहां ऐसे लोगों को बतौर विशेषज्ञ नियुक्त कर रही हैं. इसके अलावा, स्वरोजगार के तौर पर निजी क्लीनिक भी खोल सकते हैं. दंत चिकित्सा में उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद अध्यापन कार्य से भी जुड़ सकते हैं. दंत चिकित्सा को लेकर यहां रिसर्च भी कर सकते हैं.

कॉलेज - मेडिकल कॉलेज मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज, नई दिल्ली फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली ईएसआई सी डेंटल कॉलेज, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, सकिंदराबाद गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, अहमदाबाद डेंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय डॉ आर. अहमद डेंटल कॉलेज, कोलकाता

वेतनमान - दांतों के डॉक्टर का शुरुआती वेतनमान सरकारी अस्पताल में 50 हजार रुपये से ज्यादा है. जैसे-जैसे अनुभव में इजाफा होता जाता है, वेतन में बढ़ोतरी होती जाती है. सीनियर डॉक्टर के रूप में वेतनमान डेढ़ लाख से ऊपर है. इसी तरह, निजी कॉलेजों में कमाई क्लीनिक चलने पर है. यह लाख रुपये से दस लाख रुपये तक हो सकती है. इसमें खासी मेहनत और पहचान की जरूरत पड़ती है.

बनें सेना में

कानूनविद

यदि आप लॉ जानते हैं तो सेना में भी करियर बनाया जा सकता है. भारतीय सेना में जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) डिपार्टमेंट में भी काफी संख्या में भर्तियां होती हैं. यहां लॉ से ग्रेजुएट करने के बाद नौकरी मिलती है.

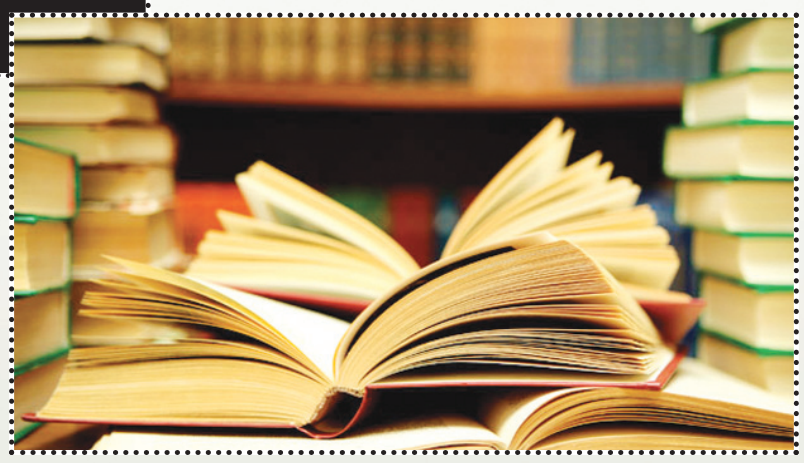

क्या है जेएजी

जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट को जेएजी नाम से जाना जाता है. इसमें योग्य आर्मी ऑफिसर लिये जाते हैं जो सेना के कानूनों के जानकार होते हैं और सेना को सभी तरह की कानूनी सहायता करते हैं.

योग्यता - भारतीय सेना हर साल लॉ ग्रेजुएट की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करती है. सेना से संबंधित डिपार्टमेंट ऑफ लीगल एडवोकेट जनरल द्वारा शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 21 से 27 वर्ष के बीच की उम्र वाले अभ्यर्थी ही पात्र हैं. इसमें विवाहित/अविवाहित दोनों तरह के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और इन पदों पर पुरुष और महिला, दोनों की भर्ती होती है. अभ्यर्थी के पास एलएलबी में कम से कम 55 फीसद अंक होना चाहिए और यह ग्रेजुएशन के बाद तीन वर्षीय या बारहवीं के बाद पांच वर्षीय डिग्री हो. इसके अलावा, अभ्यर्थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी रजिस्टर्ड होने चाहिए. इसके अलावा हाइट, वेट, टैटू आदि पर भी ध्यान दिया जाता है.

ध्यान रखें

जो भी अभ्यर्थी इस फील्ड में आने की चाहत रखते हैं, वे खुद को फिजिकली फिट रखें. वे पंद्रह मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ सकते हों. साथ ही उन्हें पुशअप, सिटअप्स, चिनअप्स और रस्सीकूद आदि आती हो.

चयन प्रक्रिया

इसमें चयन प्रक्रिया काफी लंबी होती है और यह पांच दिनों की होती है. इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होती. पहले दिन साइकोलॉजिकल एप्टीटयूड टेस्ट होता है. इन पांच दिनों में अभ्यर्थी का मेरिट का प्रदर्शन, प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम को हल करने की क्षमता, मेडिकल टेस्ट आदि प्रक्रियायें पूरी होती हैं. हर दिन की समाप्ति पर कुछ लोगों के समूह को अगले राउंड के लिए चुना जाता है और बाकी को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है. इस प्रक्रिया में तीन चरण अपनाए जाते हैं- स्क्रीनिंग, रिकमेंडेशन और मेडिकल टेस्ट. अभ्यर्थी को कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है. इसके बाद उनकी स्क्रीनिंग होती है और फिर अगले चरण के लिए शार्ट लिस्ट किया जाता है. इंटरव्यू की कई प्रक्रियाओं और फिजिकल टेस्ट भी आयोजित किया जाता है. इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी की मेडिकल जांच की जाती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है.

प्रशिक्षण - चयनित अभ्यर्थियों को चेन्नई स्थित ऑफीसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, जो 49 हफ्तों का होता है. इसे सफलतापूर्वक करने के बाद अभ्यर्थियों को कमीशन मिलता है और उनकी नियुक्ति बतौर लेफ्टिनेंट होती है. प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थी न तो शादी कर सकते हैं और न ही अपने माता-पिता के साथ रह सकते हैं. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मद्रास विश्वविद्यालय की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज की डिग्री प्रदान की जाती है.

नियुक्ति - ऑफिसर्स के शॉर्ट सर्विस कमीशन में आने पर रेग्युलर आर्मी में नौकरी 14 वर्ष की होती है. पहले उन्हें दस साल तक नौकरी पर रखा जाता है. इसके पूरा होने पर चार साल और बढ़ाये जाते हैं.

आवेदन - योग्य अभ्यर्थी आर्मी द्वारा घोषित नोटिफिकेशन में दिए गए फार्मेट को सादे कागज पर लिख कर आवेदन कर सकता है. आवेदन डार्योक्टोरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग को दिल्ली स्थित आर्मी हेडक्वार्टर्स के पते पर भेजे जाने होते हैं.

पैरा-मैडीकल कोर्सेज में संवारें कॅरिअर

यदि आपकी बारहवीं परीक्षा की श्रेणी या अंक बहुत अच्छे नहीं हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी वजह यह है कि पैरा-मैडीकल कोर्सेज में प्रवेश के लिए सी.पी.एम.टी. जैसी कठिन प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होती। डॉक्टर जब मरीज को देख लेता है उसके बाद (कुछ मामलों में डाक्टर से पहले भी) सारा काम पैरा-मैडीकल के लोग ही संभालते हैं।

मरीज के खून, पेशाब, बलगम, वीर्य, टिश्यू आदि की जांच करनी हो, उसका एक्स-रे, ई.सी.जी., ई.ई.जी., एम.आर.आई., अल्ट्रा साऊंड, सी.टी. स्कैन, टी.एम.टी.,पी.एफ.टी., मैमोग्राफी आदि इंजैक्शन व दवा देनी हो तथा इसके अलावा भी अनेक ऐसे काम हैं जिसे पैरा-मैडीकल स्टाफ ही करता है। आप्रेशन करते समय एक डाक्टर को असिस्ट करने के लिए पैरा-मैडीकल स्टाफ होता है। मैडीकल फील्ड का लगभग सारा टैक्निकल स्टाफ पैरा-मैडीकल के अंतर्गत ही आता है। इसके तहत प्रमुख कोर्स व संबंधित कार्य इस प्रकार हैं- मैडीकल लैब टैक्नोलॉजी , एक्स-रे टैक्नोलॉजी एंड रेडियोलॉजी/रेडियोग्राफी, ऑप्टोमीट्री या ऑथ्याल्मिक टैक्नोलॉजी, प्रॉस्थैटिक एवं ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग, फिजियोथैरिपी एंड ऑक्युपेशनल थैरेपी, डैंटिस्ट असिस्टैंट, स्पीच थैरेपी एंड ऑडियोलॉजी, क्लीनिकल चाइल्ड डिवैल्पमैंट, रिहैबिलिटेशन, मैडीकल ट्रांसक्रिप्शन, कम्युनिटी हैल्थ वर्कर्स कोर्स (मेल/फीमेल/मल्टीपर्पज) ऑप्रेशनल थैरेपिस्ट असिस्टैंट/ ऑप्रेशन थिएटर असिस्टैंट व टैक्नीशियन कोर्स, कॉर्डियोलॉजी टैक्नीशियन कोर्स, सी.टी. स्कैन टैक्नीशियन कोर्स।

इनके साथ ही फॉर्मेसी, नर्सिंग एवं मिडवाइफरी तथा साइकोलॉजी की गणना भी पैरा-मैडीकल के अंतर्गत ही की जाती है। उपरोक्त सभी कोर्सों में सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, बी.एससी., एम.एससी., बैचलर या मास्टर डिग्री विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रदान की जाती है।

हिरोशिमा पर गिराए परमाणु बम से 24 गुना ज्यादा खतरनाक बम बना रहा अमेरिका

वाशिंगटन। दुनिया के कई हिस्सों में अपने वर्चस्व को लगातार मिल रही चुनौती को देखते हुए अमेरिका ने एक बार फिर से परमाणु हथियारों को तेजी से विकसित करने का काम शुरू किया है। ऐसे मानचित्र जारी किए गए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद विकसित किए जा रहे एक नए तरह के परमाणु बम को अगर रूस की राजधानी मॉस्को पर गिराया जाएगा। तो उससे कितना विनाश हो सकता है। इस मानचित्र के मुताबिक रूसी राजधानी मॉस्को पर अमेरिका के नए सुपर-परमाणु ग्रेविटी बम का विनाशकारी असर हो सकता हैं।रिपोर्ट के मुताबिक इस नए बम को बी61-13 नाम दिया गया है जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 24 गुना अधिक शक्तिशाली है। पेंटागन ने इस हफ्ते घोषणा की थी कि वह एक नया परमाणु 'ग्रेविटी बम' विकसित कर रहा है, जो हिरोशिमा में विस्फोटित परमाणु बम से 24 गुना अधिक शक्तिशाली है। बी61-13 'ग्रेविटी बम' बी61 फैमिली का 13वां संस्करण है, जो गाइडेड होने के बजाय अपने लक्ष्य पर गिरता है। ग्रेविटी बम बिना गाइडेड बम होते हैं लेकिन इस नए बम में एक टेल किट होगी, जो निशाने पर गिरने में मदद करेगी और अधिक सटीकता सुनिश्चित करेगी. न्यूकमैप का उपयोग करते हुए एक सिमुलेशन का अनुमान है कि मॉस्को के ऊपर 360 किलोटन की क्षमता वाले बी61-13 बम के विस्फोट से लाखों लोग हताहत होंगे, लगभग दस लाख घायल होंगे और शहर को मीलों तक भीषण नुकसान होगा।

केन्या और सोमालिया में भारी बारिश से आई बाढ़ से 30 लोगों की मौत

लंदन । केन्या और सोमालिया में भारी बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ से कम से कम 40 लोगों की मौत हुई और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। सहायता करने वाली एजेंसियों ने इसकी जानकारी दी। सोमालिया में भयावह बाढ़ के कारण करीब 14 लोगों की मौत होने और घरों, सड़कों और पुलों के तबाह होने के बाद सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। आपातकालीन और बचाव कर्मी दक्षिणी सोमालिया के जुबालैंड राज्य के ल्यूक जिले में बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों की अनुमानित संख्या 2,400 बताई जा रही है। पड़ोसी देश केन्या में, 'केन्या रेड क्रॉस' ने कहा कि शुक्रवार से शुरू हुई भारी बारिश के बाद से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है, तटीय शहर मोम्बासा और पूर्वोत्तर काउंटी मंडेरा तथा वजीर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने जुबा और शबेले नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को बाढ़ की चेतावनी दी और सभी लोगों को वहां से निकालने का आदेश दिया। एजेंसी के प्रबंध निदेशक हसन इस्से ने बताया, सोमालिया आपदा प्रबंधन एजेंसी संकट से निपटने के लिए सुचारू रूप से काम कर रही है और लोगों को बाहर निकलाने में मदद करने के लिए उसने डोलो के वास्ते एक विमान को रवाना करने, किसमायो से लुक तक दो नाव और बारधीरे तक एक नाव भेजने की योजना बनाई है। सोमालिया में लगातार चार वर्षों तक पड़े सूखे के बाद इस साल हुई भारी बारिश ने देश को अकाल के कगार पर ला खड़ा किया है। पड़ोसी देश केन्या में केन्या रेड क्रॉस ने बताया कि भारी बारिश से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। रेड क्रॉस के मुताबिक, केन्या का बंदरगाह शहर मोम्बासा, उत्तरपूर्वी शहर मंदेरा और वजीर भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले शहर हैं। केन्या रेड क्रॉस ने बताया कि रविवार को अचानक आई बाढ़ ने 241 एकड़ कृषि भूमि को नष्ट कर दिया और 1067 जानवरों की मौत हो गई।

इस्लामी विद्रोहियों ने 11 किसानों पर हमला कर उनके सर कलम किए

मैदुगुड़ी । नाइजीरिया के उत्तरपूर्व में इस्लामी विद्रोहियों ने 11 किसानों की हत्या कर कई अन्य किसानों को अगवा किया हैं। विश्लेषकों ने इसतरह के हमलों की हालिया घटनाओं के मद्देनजर कहा कि ये घटनाएं पहले से ही बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इलाके के निवासी डौडा इब्राहिम के मुताबिक, विद्रोहियों ने येरे जिले में अपने खेतों पर काम कर रहे किसानों पर हमला कर उनके सर कलम कर दिए। फिर वे गोलबारी कर दूसरों को घायल करते हुए भाग गए। डौडा ने कहा, मारे गए किसानों में से करीब छह लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। बोरनो पुलिस के प्रवक्ता ने हमले की पुष्टि की लेकिन यह कहते हुए ज्यादा जानकारी देने से इंकार कर दिया कि हालात का जायजा लेने के लिए पुलिस प्रमुख राज्य के इलाके में मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुताबिक, इस तरह के हमलों ने संकटग्रस्त क्षेत्र में भुखमरी के खतरे को और बढ़ाया है। इस संकटग्रस्त क्षेत्र में 44 लाख लोग पहले से भुखमरी का सामना कर रहे हैं। बोरनो राज्य में किसानों पर इसतरह के हमले अक्सर होते हैं, जहां इस्लामी चरमपंथी विद्रोहियों ने पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ लड़ने और क्षेत्र में इस्लामी शरिया कानून स्थापित करने के लिए 2009 में विद्रोह शुरू किया था। नाइजीरिया में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुसार, बोको हराम समूह और इस्लामिक स्टेट समर्थित एक अलग गुट की हिंसा के कारण कम से कम 35,000 लोग मारे गए हैं और 20 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।

फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट अहद तमीमी गिरफ्तार

तेल अवीव । इजराइल-हमास जंग के बीच इजराइली सेना ने 22 साल की फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट अहद तमीमी को गिरफ्तार कर लिया है। तमीमी को हिंसा और आतंक भडक़ाने के लिए वेस्ट बैंक से अरेस्ट किया गया है। तमीमी ने 16 साल की उम्र में इजराइली सैनिक को तमाचा मारा था। तब से अहद वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के लिए हीरो बन गई। यरुशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तमीमी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर इजराइल के खिलाफ लिखा था- यहूदियों हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हेब्रोन से लेकर जेनिन तक हम तुम्हारा कत्लेआम करेंगे। तुम कहोगे कि हिटलर ने तुम्हारे साथ जो किया वो तो सिर्फ मजाक था। तमीमी ने आगे लिखा- हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। तुम्हारी खोपड़ी को खा जाएंगे।

अगले चार साल तक विश्व बैंक करेगा अंतरराष्ट्रीय निधि की निगरानी

-जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों के वित्त पोषण पर हुई बैठक

अबू धाबी। अगले चार साल तक विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय निधि की निगरानी करेगा। यह निर्णय जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों के वित्त पोषण पर हुई बैठक में लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अबू धाबी में खत्म हुई और बैठक में भाग लेने वाले लोगों ने इस बात पर सहमति जतायी है। हालांकि इस दौरान वैश्विक तापमान में वृद्धि से सबसे अधिक प्रभावित गरीब देशों की मदद करने के लिए स्थापित अंतरराष्ट्रीय निधि पर अंतिम बैठक में तनावपूर्ण बातचीत हुई। बैठक में अमेरिका और कई विकासशील देशों ने समझौते के मसौदे पर निराशा जतायी है जिसे इस महीने दुबई में होने वाली सीओपी-28 जलवायु शिखर वार्ता में हस्ताक्षर के लिए वैश्विक नेताओं के पास भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार अबू धाबी में बातचीत में शामिल हुए अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि उन्हें भले ही समझौता होने की खुशी है, लेकिन इस बात का खेद है कि कोष में दान स्वैच्छिक रूप से देने के लिए वार्ताकारों के बीच बनी सहमति अंतिम समझौते में दिखायी नहीं दी। बैठके के दौरान समझौते में निधि के इस्तेमाल के लिए बुनियादी लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है जिसमें 2024 में इसकी शुरुआत और इसे कैसे लागू किया जाएगा और कौन इसकी निगरानी करेगा जैसी बातें शामिल हैं। बैठक में बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली के जलवायु वित्त पोषण पर विशेष दूत अविनाश परसौद ने कहा कि यह समझौता चुनौतीपूर्ण लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम था। परसौद ने बैठकों में लातिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों की तरफ से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी समझौते पर पहुंचने में विफलता का सीओपी पर लंबा प्रभाव पड़ेगा। मिस्र के प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद नासिर ने कहा कि यह कुछ उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम है।

वेटिकन में एक कार्यक्रम के दौरान बच्चों से बात करते हुए पोप फ्रांसिस।

यूक्रेन को मिलेगी ईयू सदस्यता? किन शर्तों पर तैयार हो सकता है यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा की मंगलवार को बाद में बैठक होगी जिसमें यूक्रेन की सदस्यता वार्ता को औपचारिक रूप से खोलने की सिफारिश करने के बारे में निर्णय को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें कीव के लिए सकारात्मक परिणाम की उम्मीद होगी लेकिन कुछ शर्तें भी जुड़ी होंगी। ब्लूमबर्ग द्वारा देखे गए मामले और दस्तावेजों से परिचित लोगों के अनुसार, यूरोपीय आयोग संभवतः सिफारिश करेगा कि सदस्य राज्य अल्पसंख्यकों पर सुधार और कानून, भ्रष्टाचार विरोधी के साथ-साथ डी-ऑलिगार्काइजेशन और लॉबिंग पर औपचारिक बातचीत शुरू करें। यह कदम तब आया है जब रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और मॉस्को के यूरोप को अस्थिर करने के प्रयासों के बाद यूरोपीय संघ अपनी विस्तार नीति में तेजी लाना चाहता है। प्रक्रिया निजी होने के कारण पहचान उजागर न करने की शर्त पर लोगों ने कहा, राय के अंतिम शब्दों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जब पिछले जून में यूक्रेन को उम्मीदवार का दर्जा दिया गया था, तो यूरोपीय संघ ने सात कदम तय किए थे जिन्हें कीव को परिग्रहण प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने के लिए लागू करने की आवश्यकता थी। लोगों ने कहा कि यूक्रेन ने उनमें से चार मील के पत्थर पूरे कर लिए हैं। आयोग की राय, जो 8 नवंबर को जारी की जाएगी, को सदस्य राज्यों द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता होगी जब यूरोपीय संघ के नेता दिसंबर में शिखर सम्मेलन के लिए मिलेंगे। चार शर्तों की पूर्ति की सूचना पहले यूक्रेन के रेडियो स्वोबोडा ने दी थी। लोगों ने कहा कि क्या यूरोपीय संघ के नेताओं ने औपचारिक रूप से बातचीत शुरू करने का फैसला किया है, ब्लॉक की कार्यकारी शाखा कीव के समानांतर यूरोपीय कानून और यूक्रेन के बीच संरेखण के स्तर की रोड-मैपिंग और स्क्रीनिंग करके परिग्रहण प्रक्रिया की तैयारी पर तकनीकी काम शुरू कर देगी।

किंग चार्ल्स चुनाव से पहले अपराध, जलवायु पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक की योजनाएँ करेंगे निर्धारित

लंदन (एजेंसी)। किंग चार्ल्स मंगलवार को अपराध, जलवायु, आवास और अन्य कानूनों पर सरकार की योजनाएं पेश करेंगे, जो अगले साल चुनाव से पहले ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक का पहला और आखिरी तथाकथित किंग्स भाषण हो सकता है। सुनक उस कार्यक्रम का उपयोग करेंगे, जब सम्राट नए संसदीय सत्र के लिए सरकार की प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करते हुए भाषण देंगे, ताकि उनकी टीम को उम्मीद है कि इस साल की शुरुआत में उनके द्वारा बताई गई वोट-जीतने वाली नीतियां होंगी।

अपने सत्तारूढ़ कंजरवेटिव और विपक्षी लेबर पार्टी के बीच एक विभाजन रेखा बनाने की कोशिश करते हुए, जो चुनावों में बहुत आगे है, सनक से उम्मीद की जाती है कि वह 2050 तक ब्रिटेन के शुद्ध शून्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जलवायु उपायों को कम करने पर जोर देंगे। अपराध पर नकेल कसने के लिए अपने एजेंडे को भी आगे बढ़ाएंगे, ब्रिटेन के सबसे गंभीर अपराधियों के लिए अब तक शायद ही कभी इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द के उपयोग को बढ़ाने और अपराधियों को अदालत में अपने पीड़ितों का सामना करने के लिए मजबूर करने की योजना पेश करेंगे। सुनक ने भाषण से पहले एक बयान में कहा कि मैं चाहता हूं कि देश भर में हर किसी को गर्व और मन की शांति मिले जो यह जानने से मिलती है कि आपका समुदाय सुरक्षित है।

हमें हमेशा और अधिक करने का प्रयास करना चाहिए, देश के लिए सही दीर्घकालिक निर्णय लेना चाहिए और सबसे बुरे अपराधियों को लंबे समय तक बंद रखना चाहिए। सबसे घृणित मामलों में, इन दुष्ट अपराधियों को फिर कभी हमारी सड़कों पर स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। उनके कार्यालय ने कहा कि आपराधिक न्याय विधेयक कानून में स्पष्ट कर देगा कि सजा सुनाए जाने पर अपराधियों को अदालत में पेश करने के लिए उचित बल का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वे अपने पीड़ितों की बात सुन सकें।

इजराइल को धमकी देने वाले ईरान को घेरने फारस की खाड़ी में उतरा अमेरिकी बाहुबाली

-परमाणु हथियारों से लैस फ्लोरिडा पनडुब्बी हुआ तैनात

वाशिंगटन (एजेंसी)। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिका ने फारस की खाड़ी में परमाणु हथियारों से लैस फ्लोरिडा पनडुब्बी को तैनात कर दिया है। अमेरिका के इस फैसले को ईरान के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, जो लगातार यह कह रहा है कि इजरायल ने गाजा पट्टी पर हमले नहीं रोके, तब हम युद्ध में उतरने को तैयार हैं। इसके बाद अमेरिका के कदम को ईरान की घेरेबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा यह अमेरिका की ओर संकेत है कि यदि ईरान जारी जंग में अपने कदम आगे बढ़ाए, तब फिर अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। इस मिसाइल की तैनाती की पुष्टि खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकारियों ने की है।

इस अमेरिकी सबमरीन में एक साथ 154 मिसाइलों को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा नेवी के 66 सील कमांडो भी इसमें तैनात रहते हैं। इस साल यह दूसरा मौका है, जब अमेरिका ने अपनी मारक पनडुब्बी को फारस की खाड़ी में तैनात किया है। अप्रैल में अमेरिका नौसेना ने इस पनडुब्बी की एक तस्वीर शेयर की थी, जिसे भूमध्य सागर में तैनात किया गया था। अमेरिका के इस कदम ने फारस की खाड़ी में तनाव जरूर पैदा कर दिया है। ईरान के साथ लंबे समय से अमेरिका के रिश्ते खराब हैं। इसकारण इजरायल और हमास युद्ध में दोनों अलग-अलग पालों में दिख रहे हैं। एक ओर ईरान को इजरायल पर हमला करने वाले हमास और हिजबुल्लाह के समर्थक के तौर पर देखा जाता है, तब वहीं अमेरिका हमेशा से इजरायल समर्थक रहा है। हमास के हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने कहा था कि इजरायल को अपनी रक्षा का हक है। हालांकि जब इजरायली हमलों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक भी मारे जाने लगे तब पूरी दुनिया में युद्ध विराम की मांग उठी। इस पर भी अमेरिका ने इजरायल से यह नहीं कहा है कि वह युद्ध रोके, लेकिन यह जरूर कहा कि हमास के आतंकियों के अपराध की सजा फिलिस्तीन के नागरिकों को नहीं दी जा सकती।

नाइजीरिया में कनाडा हाईकमीशन पर हमला, दो की मौत

अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में एक जोरदार धमाका हुआ है। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक एफसीटी फायर सर्विस के अनुसार अबूजा में कनाडाई उच्चायोग में विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई और अन्य दो को अस्पताल भेजा गया। एफसीटी फायर सर्विस के मर्सी डगलस ने बताया, जनरेटर बिल्डिंग के अंदर मौजूद एक टैंकर में विस्फोट हो गया... जनरेटर का प्रबंधन करने वाली कंपनी के लिए काम करने वाले दो लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा, विस्फोट से इमारत के बाहर दो लोग घायल हो गए। वे अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। डगलस ने कहा, अबुजा में अग्निशमन सेवा ने आग पर काबू पा लिया और दोपहर एक बजे तक वे स्टेशन पर वापस आ गए।

युद्ध में उतरने से पहले ही रूस के जंगी जहाज को यूक्रेन ने किया क्षतिग्रस्त

-रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया कंफर्म, यूक्रेन ने 15 क्रूज मिसाइलों से किया हमला

गाजा (एजेंसी)। कीव (ईएमएस)। रूस के एक युद्धपोत को जंग में उतरने से पहले ही यूक्रेन ने क्षतिग्रस्त कर ?दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूक्रेन के वायु सेना के कमांडर मायकोला ओलेशचुक ने दावा किया है कि उसने युद्धपोत को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बात को रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कंफर्म किया गया है। इजरायल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के साथ ही यूक्रेन का यह बड़ा दावा सामने आया है। कि उसने रूस के एक क्रूज मिसाइल कैरियर को इस्तेमाल में आने से पहले ही बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की सेना के अफसरों के मुताबिक यूक्रेन ने एक ऐसे रूसी मिसाइल कैरियर पर हमला किया, जो ब्लैक सी के रूसी बेड़े में शामिल भी नहीं हुआ था। यूक्रेन की वायु सेना के कमांडर मायकोला ओलेशचुक ने कहा कि यूक्रेन ने क्रीमिया के रूसी कब्जे वाले प्रायद्वीप में जालिव शिपयार्ड को निशाना बनाया। यूक्रेन ने इस बात का संकेत दिया कि हमले के लिए फ्रांस की तरफ से दी घई स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इन मिसाइलों को स्टॉर्म शैडो मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है।

ओलेशचुक ने बताया कि रूस ने अपने सबसे आधुनिक युद्धपोतों में से एक को जालिव में रखा था। यह युद्धपोत कैलिब्रे क्रूज मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। हालांकि, उन्होंने जहाज का नाम नहीं बताया। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी अपने एक जहाज के क्षतिग्रस्त होने की बात को स्वीकार किया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन ने शिपयार्ड पर 15 क्रूज मिसाइलों की बौछार की थी। मंत्रालय ने दावा किया कि रूस ने 13 मिसाइलों को मार गिराया है। हालां?कि रूस के स्वीकार करने के बाद यूक्रेन के मंत्रिस्तरीय सलाहकार एंटोन गेराशचेंको ने एक वी?डियो फुटेज भी पोस्ट किया है, जिसमें शिपयार्ड में एक बड़ी आग दिखाई गई है।

यूक्रेन की वायु सेना के कमांडर मायकोला ओलेशचुक ने कहा कि उनका ऑपरेशन सफल रहा। उन्होंने बताया कि छोटी मिसाइल ले जाने में सक्षम जहाज आस्कोल्ड पर कम से कम तीन हमले हुए। यूक्रेनी नौसैनिक कप्तान एंड्री रायजेंको ने दावा किया कि क्षतिग्रस्त जहाज संभवतः कार्वेट आस्कोल्ड था। बताया जा रहा है ?कि जहाज अब भी तैर रहा है, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। रूसी बेड़े की गतिविधियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ब्लैक सी फ्लीट ने बताया कि आस्कॉल्ड एक छोटा मिसाइल वाहक है, जो आठ कलिब्र क्रूज मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है।

रेडियो इंडिया के प्रबंध ने जस्टिन ट्रूडो को लिखा पत्र, सिख फॉर जस्टिस को आंतकी संगठन घोषित करे

-गुरपतवंत पन्नू जैसे लोगों पर एक्शन लिया जाए

सरे (एजेंसी)। प्रसिद्ध मीडिया संगठन रेडियो इंडिया (सरे) के प्रबंध निदेशक मनिंदर सिंह गिल ने कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को पत्र लिखकर किसी विशेष पार्टी के बजाय पूरे पंजाबी सिख समुदाय के हितों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया हस्ती के रूप में, यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे कनाडा में भारतीय-कनाडाई समुदाय के सामने आने वाली सुरक्षा चिंताओं को सक्षम सरकार के ध्यान में लाएं।

गिल ने कहा, कनाडा में भारतीय-कनाडाई समुदाय के खिलाफ नफरत और धमकी की हरकतें खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं। कनाडा में दिनदहाड़े इंडो-कनाडाई समुदाय पर शारीरिक हमले आम हो रहे हैं। सरे में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को लेकर उन्हें खुद भी शारीरिक हमले और जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन देश में कानून के तहत उन्हें अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, जबकि ये हमले 19 मार्च 2023 को पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुए थे।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी खतरे अब खुला आतंकवाद बन चुके हैं, क्योंकि सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के गुरपतवंत पन्नू ने भारतीय समुदाय को एयर इंडिया पर हमला करने की खुलेआम धमकी दी है। पन्नू ने सिख समुदाय को खुलेआम चेतावनी दी है कि वे एयर इंडिया से यात्रा न करें क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये आतंकी धमकियां एयर इंडिया आतंकी हमले के 329 कनाडाई पीड़ितों को परेशान करती हैं, जिनके परिवार के सदस्य इस घटना में मारे गए थे। गिल ने कहा कि पन्नू की हालिया धमकियां उन परिवारों के घावों पर नमक छिड़कने के समान हैं जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है।

गिल ने कहा, झूठी सूचना फैलाकर किसी विमान की सुरक्षा को खतरे में डालना कनाडाई आपराधिक संहिता की धारा 77 के तहत आजीवन कारावास की सजा वाला अपराध है। कनाडा की आपराधिक संहिता की धारा 319(2) के तहत लोगों के एक समूह के खिलाफ जानबूझकर नफरत भड़काना एक गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय इस बात से व्यथित है कि गुरपतवंत पन्नू जैसे लोग कनाडा में कानूनी छूट का आनंद क्यों ले रहे हैं, जहां उन्हें अपने घृणित और आतंकवादी बयानों के लिए कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ रहा है।

अंत में, गिल ने कहा, कनाडा के कानून के शासन में, जहां सिख फॉर जस्टिस को एक आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, सरकार पर नफरत फैलाने वाले भाषण और आतंकवादी धमकियां देकर एयर इंडिया के यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया जाना चाहिए। पन्नू पर मुकदमा चलाना चाहिए।

रूस ने किया था बैकऑफ, अब नाटो ने शीत युद्ध की सुरक्षा संधि को किया निलंबित

(एजेंसी)। नाटो ने मंगलवार को रूस के सौदे से बाहर निकलने के जवाब में शीत युद्ध-युग की एक प्रमुख सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित करने की घोषणा की। गठबंधन ने कहा कि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले उसके सदस्य अब समझौते में अपनी भागीदारी रोक रहे हैं। नाटो के 31 सहयोगियों में से अधिकांश ने यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के प्रतिद्वंद्वियों को आपसी सीमाओं पर या उसके निकट सेना इकट्ठा करने से रोकना था। इस पर नवंबर 1990 में हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन दो साल बाद तक इसे पूरी तरह से अनुमोदित नहीं किया गया था।

नाटो ने कहा कि ऐसी स्थिति जिसमें मित्र राष्ट्र पार्टियाँ संधि का पालन करती हैं, जबकि रूस नहीं करता, अस्थिर होगी। रूस के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को पहले घोषणा की थी कि मॉस्को ने अपनी वापसी को अंतिम रूप दे दिया है। जवाब में नाटो ने कहा, जिन सहयोगियों ने हस्ताक्षर किए थे। वे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने अधिकारों के अनुसार, जब तक आवश्यक हो, सीएफई संधि के संचालन को निलंबित करने का इरादा रखते हैं। यह सभी नाटो सहयोगियों द्वारा पूरी तरह से समर्थित निर्णय है। नाटो ने रेखांकित किया कि उसके सदस्य सैन्य जोखिम को कम करने और गलत धारणाओं और संघर्षों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भारत का विकास दर अनुमान बढ़ाया, चीन का घटाया

-कई विकसित देश वर्तमान में आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे

वाशिंगटन (एजेंसी)। चीन-अमेरिका सहित कई विकसित देश वर्तमान में आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। वहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भारत के विकास दर अनुमान को बढ़ा रही है। ग्लोबल रेटिंग फिच ने भारत के आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 5.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया है। वहीं चीन की जीडीपी ग्रोथ 5.3 प्रतिशत से घटाकर 4.6 प्रतिशत कर दिया है। इससे साफ होता हैं कि कैसे विदेशी कंपनियां भू-राजनीतिक तनाव और अन्य जगहों पर उच्च ब्याज दरों के कारण देश से पैसा खींच रही हैं। देश के विदेशी मुद्रा प्रशासन ने कहा कि भुगतान संतुलन में चीन की प्रत्यक्ष निवेश देनदारियों में तीसरी तिमाही में 11.8 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। यह उपाय चीन में विदेशी स्वामित्व वाली संस्थाओं से जुड़े मौद्रिक प्रवाह को रिकॉर्ड करता है। अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि भुगतान संतुलन के उपाय द्वारा एफडीआई में गिरावट विदेशी कंपनियों द्वारा चीन में किए गए मुनाफे को देश में फिर से निवेश करने की कम इच्छा को दर्शाती है। ऐसा पश्चिम के साथ तनावपूर्ण संबंधों और विदेशों में नकदी रखने के बढ़ते आकर्षण के कारण है। उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ ब्याज दरें बढ़ा रही हैं, जबकि चीन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए उनमें कटौती कर रहा है। पेंथियन मैक्रोइकॉनॉमिक्स के मुख्य चीन अर्थशास्त्री डंकन रिगले ने कहा कि संभवतः यह विदेशी कंपनियों को चीन से कमाई वापस लाने को दर्शाता है, जबकि पहले उन्होंने इसे पुनर्निवेशित किया था। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ, विशेष रूप से अमेरिकी कंपनियाँ, चीन के विकल्पों का उपयोग करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से कॉन्फ़िगर कर रही हैं। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह का अन्य मुख्य उपाय, इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में 920 बिलियन युआन (125.8 बिलियन) तक पहुंच गया, जो 2022 की इसी अवधि की तुलना में 8.4 प्रतिशत कम है। चीन में निर्यात-उन्मुख और औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाली विदेशी कंपनियों ने इस साल अपने मुनाफे में गिरावट देखी है, क्योंकि चीन के निर्यात के मूल्य में गिरावट आई है और संपत्ति में गिरावट के कारण औद्योगिक वस्तुओं की मांग प्रभावित हुई है। चीन के सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, चीन में विदेशी निवेश वाली औद्योगिक कंपनियों का मुनाफा पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 2023 की पहली तीन तिमाहियों में 10.5 प्रतिशत गिर गया।

मंत्री छगन भुजबल को फिर जान से मारने की धमकी, सरकारी आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ी

मुंबई। ओबीसी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने मराठा समुदाय को कुनबी सर्टिफिकेट देने के फैसले का सार्वजनिक तौर पर विरोध किया है. उनकी भूमिका के कारण मराठा समाज आक्रामक हो गया है. बताया गया है कि अज्ञात लोगों ने भुजबल को फोन कर फिर जान से मारने की धमकी दी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने छगन भुजबल के सरकारी आवास पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी है. मराठा आंदोलनकारी मनोज जारांगे पाटिल ने मराठा समुदाय को तुरंत कुनबी प्रमाणपत्र देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी. राज्य भर के मराठा समाज के लोगों ने उनके आंदोलन का जोरदार समर्थन दिया। जारांगे के आह्वान के बाद राज्य में भूख हड़तालों का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ जगहों पर आंदोलन को झटका भी लगा. इस बीच राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने जारांगे से मुलाकात की और जल्द से जल्द आरक्षण देने का आश्वासन दिया. राज्य सरकार के आश्वासन के बाद जारांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली. हालांकि सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने शिंदे सरकार के इस फैसले का विरोध किया. मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण दिया जाए, यह कई वर्षों से हमारा रुख रहा है। लेकिन भुजबल ने कुनबी सर्टिफिकेट देने के फैसले का सीधा विरोध करते हुए कहा कि इससे हमारे आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. ओबीसी समाज को इस फैसले का पूरी ताकत से विरोध करना चाहिए. छगन भुजबल ने कहा, अन्यथा, एक बार जब ओबीसी समुदाय अपना आरक्षण खो देता है, तो इसे दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता है। इस बीच छगन भुजबल ने आरोप लगाया है कि मराठा समुदाय के कुछ लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. इसी वजह से भुजबल के सरकारी आवास के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

मणिपुर में गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मियों समेत 5 घायल

इम्फाल। मणिपुर में मंगलवार को ताजा हिंसा भड़क उठी, जब कांगचुप पहाड़ी पर भारी गोलीबारी में पांच लोग घायल हो गए। घायलों में दो पुलिस कर्मी और तीन ग्रामीण स्वयंसेवक शामिल हैं, और उन्हें इलाज के लिए इंफाल अस्पताल ले जाया गया। इंफाल पश्चिम जिले की सीमा पर स्थित कांगचुप गांव में सुबह गोलीबारी शुरू हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक, सुबह करीब 9.10 बजे इलाके में गोलियों की आवाज सुनी गई। घटनाक्रम इंफाल पश्चिम जिले से दो किशोर लड़कों के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के बाद पूर्वोत्तर राज्य के कई हिस्सों में तनाव फैलने के एक दिन बाद आया है। उनके परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने कहा कि 16 और 19 साल की उम्र के लड़के 5 नवंबर को सुबह दोपहिया वाहन पर सेकमाई की ओर गए थे, और समय पर घर नहीं लौटे। जब उनसे संपर्क किया गया तो उनके मोबाइल फोन से भी कोई जवाब नहीं मिला। बाद में उनके परिवारों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और राजभवन में मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके और मणिपुर रॉयल पैलेस में मणिपुर के राजा, राज्यसभा सांसद लीशेम्बा सनाजाओबा से भी मुलाकात की। परिवारों को उनके लापता होने में सशस्त्र कुकी बदमाशों का हाथ होने का संदेह है और उन्होंने मणिपुर सरकार से लापता लड़कों को ढूंढने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इस बीच, सेकमाई इलाके के सीसीटीवी फुटेज में दो लड़के अपनी मोटरसाइकिल पर कांगलाटोम्बी की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेनापति ऑयल पंप के पास मोबाइल फोन सिग्नल ट्रेस किए जाने के बावजूद, इस रिपोर्ट को लिखे जाने तक वे गायब हैं। कांगपोकपी जिला पुलिस, असम राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) लड़कों के लापता होने से जुड़े होने के संदेह वाले क्षेत्रों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। 3 मई को मणिपुर में भड़के जातीय संघर्ष में 180 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई सौ घायल हो गए। झड़पें पहाड़ी जिलों में आयोजित 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के बाद शुरू हुईं, जहां निवासियों ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मैतेई समुदाय के अनुरोध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की तैयारी शुरु : प्रस्ताव नगर निगम से पास

अलीगढ़। यूपी के अलीगढ़ जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम से पास हो गया है। अब फैसले पर प्रशासन की मुहर का इंतजार है। अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिंघल ने मंगलवार को कहा कि सोमवार को हुई बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अब यह प्रस्ताव प्रशासन को भेजा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इस पर संज्ञान लेकर अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की हमारी मांग को पूरा करेगा। यह मांग लंबे समय से उठा रही है। तालानगरी का नाम बदलने का ये प्रस्ताव बीजेपी पार्षद संजय पंडित के सुझाव पर पास किया गया है। अलीगढ़ नगर निगम की बैठक में काफी हंगामा भी हुआ। हंगामे के बीच बीजेपी पार्षद ने जिले का नया नाम हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव दिया। ये पहला मौका नहीं है जब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग की गई. इससे पहले भी बीजेपी नेता इस तरह की मांग करते आए हैं। बात दें कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक अहम व्यापारिक केंद्र है और अपने ताला उद्योग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अलीगढ़ के ताले दुनिया भर में निर्यात किये जाते हैं। इसके अलावा अलीगढ़ अपने पीतल के हार्डवेयर और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ देश का एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र भी है। यहां 100 से अधिक स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान हैं। जिसमें अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी शामिल है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने कृत्रिम बारिश करने की तैयारी

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में लगातार हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसकारण राजधानी की आबोहवा खराब हो गई है, और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसी बीच कानपुर आईआईटी से एक राहत भरी खबर है। दरअसल आईआईटी कानपुर की ओर से दूषित हवा से प्रदूषण और धूल के कणों को साफ करने के लिए क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश के उपयोग का प्रस्ताव दिया गया है। अगर ऐसा हुआ तब दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराकर प्रदूषण कम करने का प्रयास होगा है। दरअसल कानपुर आईआईटी बीते पांच सालों से कृत्रिम बारिश के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाने के लिए काम कर रहा है। पिछले साल जुलाई में इसका सफल परीक्षण किया गया था, रिपोर्ट कहती है कि शोधकर्ताओं द्वारा क्लाउड सीडिंग के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) सहित अन्य सरकारी विभागों से जरूरी अनुमति ले ली है। कानपुर आईआईटी के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ मनिंदर अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार ने उनसे संपर्क किया है, और दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रदूषण लेवल को लेकर सीआईआई (कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) के साथ मिलकर पिछले दो महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। सीआईआई इसे लेकर बहुत सक्रिय है। इतना ही नहीं दिल्ली और केंद्र सरकार के साथ को-ऑर्डिनेट कर रही है।

कृत्रिम बारिश से कम होगा प्रदूषण!

इस सवाल पर प्रोफेसर मनिंदर कहते हैं कि इस कृत्रिम बारिश से वातावरण के डस्ट पार्टिकल बह जाते हैं। ये स्थायी नहीं होता अस्थायी होता है। हमें प्रदूषण के जो सोर्स हैं उन पर एक्शन लेना होगा। प्रोफेसर ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर का क्षेत्र बहुत बड़ा है, किस क्षेत्र में बादल होगा और किस स्थिति में होगा उसके आधार पर ही तय हो पाएगा कि किस क्षेत्र में बारिश कराई जा सकती है, चूंकि इस प्रक्रिया में एयरक्राफ्ट, उसका ईंधन, मेंटिनेंस सहित कई अन्य चीजों पर खर्च होता है, तब इसकी लागत भी काफी आती है।

ज्ञानवापी परिसर सर्वे में मिली खंडित मूर्तियां, चिह्न, आकृतियां, कोषागार के डबल लॉकर में रखा गया

वाराणसी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को 17 नवंबर तक पेश करना है। वहीं वाराणसी जिला अदालत द्वारा एएसआई (एएसआई) सर्वे के दौरान मिले साक्ष्य को सुरक्षित रखने की कार्यवाही को पूर्ण किया गया है। जिला अदालत की ओर से आदेश के अनुसार सभी साक्ष्यों की गणना करते हुए उन्हें क्रमबद्ध तरीके से जिला प्रशासन को सौंप दिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा वाराणसी के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कोषागार के डबल लॉकर में साक्ष्य को सुरक्षित रख दिया गया है। इस मामले में अधिवक्ता सुभाष चंदन चतुर्वेदी ने बताया कि सभी कानूनी कार्यवाही और दलीलें साक्ष्य व सबूत के आधार पर ही पूर्ण की जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि सर्वे के दौरान मिले सभी साक्ष्य और सबूत को सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए।

धारा 135 के तहत शराब घोटाले में हो सकती है केजरीवाल की गिरफ्तारी

-ईडी ने जारी किया था समन, पत्र से जवाब देकर 2 नवंबर को नहीं हुए उपस्थित

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। उन्होंने ईडी द्वारा जारी समन का पत्र लिखकर जवाब दिया, साथ ही उसे गैर कानूनी भी ठहराया था। अब यदि धारा 135 के तहत क्रिमिनल केस बनता है तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि सिविल मामले में तो पीएम या सीएम या संसद के सदस्यों को गिफ्तारी से छूट है, लेकिन क्रिमिनल मामलों में नहीं है। बता दें कि ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले में समन जारी किया है। उन्हें ये समन कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जारी हुआ है। वहीं आप नेता आतिशी ने उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। ऐसे में यह जानना भी जरुरी है कि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के नियम क्या हैं? दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को अब प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। केजरीवाल को 2 नवंबर को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर जवाब दिया और ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। इससे पहले सीबीआई ने अप्रैल में उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की थी।

इधर आम आदमी पार्टी ने आंशका जताई है कि ईडी कभी भी मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने यह दावा किया था। आतिशी ने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। दसअसल कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर की धारा 135 के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट मिली है। ये छूट सिर्फ सिविल मामलों में है, क्रिमिनल मामलों में नहीं है।

इस धारा के तहत संसद या विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदस्य को गिरफ्तार करना है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति से मंजूरी लेना जरूरी है। साथ ही सत्र से 40 दिन पहले, उस दौरान और उसके 40 दिन बाद तक ना तो किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही हिरासत में लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, संसद परिसर या विधानसभा परिसर या विधान परिषद के परिसर के अंदर से भी किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं ले सकते, क्योंकि अध्यक्ष या सभापति का आदेश चलता है।

मिलीजुली होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, दिसंबर में शुरु होने के संकेत

नई दिल्ली। दिसंबर में कांग्रेस एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा शुरु करने जा रही है। हालांकि यह यात्रा हाईब्रिड अर्थात मिलीजुली होगी। संभवत- यह यात्रा इसी साल दिसंबर में शुरु हो सकती है, जोकि अगले साल फरवरी तक चलेगी। इस तरह से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की तैयारी कर रही है। इस बार यात्रा पहले की तरह पैदल नहीं की जाएगी, बल्कि इसे हाईब्रिड करने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी, जिसका समापन 30 जनवरी 2023 को कश्मीर में हुआ था। बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बाद अपने अनुभव साझा किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके घुटनों में दर्द रहता है, जिसकी वजह से चलने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जनता से मिले प्यार से वो अपने दर्द भूल गए और उन्होंने यात्रा पूरी कर ली थी। इसीलिए कांग्रेस ने यात्रा का दूसरा चरण हाईब्रिड चुना ताकि राहुल गांधी और अन्य नेताओं को दिक्कत न हो। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। जिसमें राहुल गांधी, पार्टी के कई नेताओं के साथ 4,000 किलोमीटर से अधिक लंबी यात्रा की थी। उनकी यह यात्रा दक्षिण में कन्याकुमारी से शुरू हुई थी जोकि 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर के लालचौक पर तिरंगा फहराकर खत्म हुई। यह यात्रा तमिलनाडु से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब होते हुए कश्मीर पहुंची थी। इस यात्रा से राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ-साथ विरोधियों का भी ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे थे। इस मार्च में कमल हासन, पूजा भट्ट, रिया सेन, स्वरा भास्कर, रश्मि देसाई, आकांक्षा पुरी और अमोल पालेकर जैसी फिल्म और टीवी हस्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी देखी गई थी।

कांग्रेस- सपा पर संजय निषाद ने साधा निशाना,

बताया एक-दूसरे के खून के प्यासे

लखनऊ (एजेंसी)। मंत्री संजय निषाद ने कांग्रेस-सपा को आड़े हाथों लेते हुए बयान जारी किया है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन में सभी पार्टियां एक दूसरे के खून की प्यासी हैं। गौरतलब है कि देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। इन चुनावों को लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को हराने के लिए बने विपक्षी दलों के गठबंधन में मप्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सीट नहीं दिए जाने और सपा के प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के अपने प्रत्याशी उतारने के कारण दरार पड़ती नजर आ रही है। इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। इसी क्रम में एनडीए गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने इंडिया गठबंधन को लेकर प्रतिक्रिया दी है।

गौरतलब है कि इन दिनों समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जनसभा में संबोधन के दौरान बीजेपी के साथ ही कांग्रेस को निशाना बनाया है और कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज तक बता दिया है। ऐसे में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ संजय निषाद का कहना है कि विपक्षी पार्टियों ने यह साबित कर दिया है कि भारत में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने लड़ने वाला अभी कोई उम्मीदवार ही नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बैठकें शुरू की थी, मैंने उसी समय कह दिया था कि बहुते जोगी मठ उजाड़ हैं।यह सभी लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे हैं।

डॉ संजय निषाद ने कहा कि उनकी नीति षड़यंत्रकारी और रवैया उपेक्षात्मक रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की षड़यंत्रकारी और उपेक्षात्मक रवैये के कारण उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी पहले भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर उसका नुकसान सह चुकी है। वह चाहे तो एक बार फिर से कांग्रेस के हाथों धोखा खा सकती है। ये बिना दूल्हे की बारात है और यही कारण है कि 45 पार्टियों ने भाजपा के पीएम मोदी के साथ जाने का फैसला किया है।

आतंकी पन्नू की धमकी पर अलर्ट, पंजाब में एयरपोर्ट पर विजिटर एंट्री बैन

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत में नागरिक उड्डयन के लिए नियामक प्राधिकरण, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) ने दिल्ली और पंजाब में हवाईअड्डा संचालकों से आगंतुकों को हवाईअड्डा प्रवेश पास जारी करना बंद करने को कहा है, यह कदम सिख्स फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नून के बाद उठाया गया कदम है। एसजेएफ) ने रविवार को एयर इंडिया की उड़ानों के यात्रियों को धमकी देते हुए एक वीडियो जारी किया। पन्नून ने 19 नवंबर को आईसीसी विश्व कप फाइनल के दिन एयर इंडिया की उड़ान को उड़ाने की धमकी दी।

बीसीएएस आदेश में कहा गया है कि आईजीआई (इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय) हवाई अड्डे (दिल्ली में) के टर्मिनल भवन में आगंतुकों के प्रवेश के लिए टीएईपी (अस्थायी हवाईअड्डा प्रवेश पास) जारी करना और आगंतुकों के प्रवेश टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि बीसीएएस का आदेश लागू कर दिया गया है। हमने आदेश लागू कर दिया है और परिचालन कार्य में शामिल लोगों को छोड़कर सभी एईपी 30 नवंबर तक निलंबित रहेंगे।

बीसीएएस ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा हवाईअड्डों, हवाई पट्टियों, हवाई क्षेत्रों, वायु सेना स्टेशनों, हेलीपैड, फ्लाइंग स्कूलों और विमानन जैसे नागरिक उड्डयन प्रतिष्ठानों पर खतरे के बारे में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा लगातार साझा किए गए खतरे के संदेशों के बाद एहतियाती उपाय के रूप में यह कदम उठाया जा रहा है। नियामक प्राधिकरण ने कहा कि हवाई अड्डे पर सुरक्षा एजेंसी को अनिवार्य रूप से सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक (एसएलपीसी) रखना होगा।

सांप के जहर मामले में एल्विश यादव को नोटिस, जल्द होगी पूछताछ

नई दिल्ली (एजेंसी)। नोएडा पुलिस ने मंगलवार को यूट्यूबर एल्विश यादव को सांप के जहर के मामले में उनके सामने पेश होने का नोटिस दिया। जल्द ही उनसे पूछताछ होने की संभावना है। सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 2' जीतने के बाद प्रसिद्धि पाने वाले यादव पर दिल्ली-एनसीआर में एक पार्टी में मनोरंजन के उद्देश्य से सांप का जहर उपलब्ध कराने के आरोप में पांच अन्य लोगों के साथ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस इस मामले में राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ नाम के अन्य पांच लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

भाजपा सांसद मेनका गांधी की पार्टी पीपल फॉर एनिमल्स द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, उन्होंने एक 'स्टिंग ऑपरेशन' किया, जहां उन्होंने यादव से संपर्क किया और उनसे एक रेव पार्टी आयोजित करने और कोबरा जहर प्राप्त करने के लिए कहा। एल्विश ने हमें एक राहुल का नाम दिया जिससे हमने संपर्क किया। उन्होंने कहा कि हम जहां चाहें वहां जहर का प्रबंध कर सकते हैं। इसके बाद वह वेनम को लेकर सेक्टर 51 बैंक्वेट हॉल में आया। इसके बाद नोएडा पुलिस डीएफओ के साथ कार्यक्रम स्थल पर आई और आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया।

इस बीच, यादव आरोपों का खंडन करते हुए कहते रहे हैं कि वे निराधार और फर्जी हैं। जबकि YouTuber जांच में सहयोग करने के लिए सहमत हो गया है, उसने भाजपा सांसद के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने की भी धमकी दी है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस व बीजेपी में कांटे की टक्कर, मिजोरम में त्रिकोणीय मुकाबला

-राज्यों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

नई दिल्ली (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर को शुरु हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 20 सीटों पर 25 महिलाओं सहित 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगा। इस बीच मिजोरम में 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक ही चरण में आज मतदान हो रहे है। जहां छत्तीसगढ़ में सत्तारुढ़ कांग्रेस व बीजेपी में कांटे की टक्कर होने वाली है, वहीं मिजोरम में त्रिकोणीय मुकाबला होने की बात कही जा रही है। बता दें ?कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा, जबकि राजस्थान और तेलंगाना में क्रमशः 25 और 30 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा। सभी राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इन विधानसभा चुनावों को केंद्र में भाजपा, नवगठित विपक्षी भारतीय गुट और क्षेत्रीय दलों के लिए एक अग्निपरीक्षा के रूप में देखा जाता है, और उनके परिणाम आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीतियों को प्रभावित करने के लिए निश्चित हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच है।

यहां पर कांग्रेस राज्य में लगातार दूसरे कार्यकाल की उम्मीद कर रही है, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव बुक ऐप से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। भाजपा इस विवाद को भुनाने और कांग्रेस की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हालाँकि, मिज़ोरम, मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ), ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) और कांग्रेस के साथ प्राथमिक दावेदारों के रूप में अधिक विविध राजनीतिक परिदृश्य देखता है। भाजपा मिजोरम में भी 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने चार सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता डॉ. रमन सिंह और कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख और सांसद दीपक बैज शामिल हैं। मिजोरम में, एमएनएफ नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा, जेडपीएम के संस्थापक लालदुहोमा और राज्य कांग्रेस प्रमुख लालसावता प्रमुख हैं।

बता दें कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से कई वादे किए हैं, जिनमें जातिगत जनगणना कराना, किसानों को ऋण माफी प्रदान करना, गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी की पेशकश करना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। दूसरी ओर, भाजपा ने कथित भ्रष्टाचार और धान की बढ़ती कीमतों को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस पर निशाना साधा है। यहां शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। छत्तीसगढ़ में 60,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है और नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में 600 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

बिहार में जातिवार जनगणना का चौंकाने वाला आंकड़ा, सवर्णों में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या ताकतवा भूमिहार

-पिछड़ों में सबसे ज्यादा गरीब नाई

पटना (एजेंसी)। बिहार में जातिवार जनगणना के आधार पर आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट भी पेश की गई है। विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। जिसमें प्रभुत्व वाली जातियों की भी बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सवर्णों में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या भूमिहार बिरादरी में है, जहां 27.58 फीसदी लोग गरीब हैं। वहीं पिछड़ों की बात करें तब 35 फीसदी की संख्या के साथ यादव बिरादरी में गरीबों का बड़ा आंकड़ा है। कुशवाहा समाज में 34 फीसदी लोग गरीब हैं। इतना ही नहीं कुर्मियों में 29 फीसदी गरीबी रेखा से नीचे हैं। पिछड़ों में सबसे ज्यादा गरीब नाई हैं, जिनकी 38 फीसदी आबादी 6000 रुपये से कम में जीवनयापन कर रही है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58 फीसदी गरीब परिवार हैं। अनुसूचित जाति में 42.93 फीसदी गरीब परिवार हैं और अनुसूचित जनजाति में 42.70 फीसदी परिवार गरीबी के दलदल में फंसे हैं। इसके अलावा राज्य में सबसे ज्यादा गरीब मुसहर समुदाय से हैं। इस बिरादरी के 54 फीसदी लोग गरीबी में जीवन गुजर रहे हैं। अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा 38 फीसदी नाई गरीब हैं। दूसरे नंबर पर नोनिया हैं, जिनमें 35 फीसदी लोग गरीब हैं। इसके अलावा कहार, धानुक और मल्लाह समुदायों की भी 34 फीसदी आबादी गरीब है। 33 फीसदी कुम्हार, 29.87 फीसदी तेली और 33 फीसदी के करीब कानू भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजार रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार के सर्वे में कुल 63 फीसदी आबादी पिछड़ों और अत्यंत पिछड़ों की है। सर्वे रिपोर्ट में जनरल से लेकर एससी तक सभी जातियों में बड़ी संख्या में गरीब पाए जाने से यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि अब आरक्षण किस आधार पर देने की चर्चा होगी। अब तक सरकार यह कहती रही है कि पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले क्योंकि उनमें गरीबों की संख्या अधिक है।

सवर्णों में कौन सबसे खुशहाल, भूमिहारों के आंकड़े ने चौंकाया

सवर्णों में सबसे अच्छी स्थिति कायस्थों की है, जिनकी महज 13.83 फीसदी आबादी ही गरीब है। 25 फीसदी ब्राह्मण परिवार गरीब हैं, जबकि राजपूतों में भी यह औसत 24.89 प्रतिशत यानी करीब 25 का ही है। इसके अलावा मुस्लिम सामान्य वर्ग में शामिल शेख

25 फीसदी गरीब हैं, पठानों में यह आंकड़ा 22 फीसदी हैं। इसके अलावा सैयद 17 फीसदी ही गरीब हैं। सबसे ज्यादा गरीब भूमिहार जाति से हैं। यहां 27 फीसदी लोग गरीब हैं। दरअसल यह आंकड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि बिहार में भूमिहारों को ताकतवर जाति में शुमार किया जाता है।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पुलिस आयुक्तके मार्गदर्शन के बाद कुछ आरोपियों ने अब अपराध छोड़कर सुधरने का संकल्प लिया

'मैं अब कोई अपराध नहीं करना चाहता',चोरी के अपराध में पकड़े गए आरोपी ने सिसकते हुए कहा

शहर के विभिन्न 36 पुलिस थानों के एक हजार आरोपियों को इकठ्ठा कर मार्गदर्शन दिया गया

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

दिवाली का त्यौहार शुरू हो चुका है और सूरत शहर पुलिस शहर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए गंभीर अपराधों में शामिल लगभग 1 हजार आरोपियों की आज अठवालाइन्स स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में परेड कराई गई। जिसमें आरोपी के वर्तमान निवास, कार्य सहित सभी प्रकार की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की गई। इतना ही नहीं बल्कि आरोपियों को सूरत सिटी पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर द्वारा विशेष मार्गदर्शन दिया गया ताकि आरोपी अपराध का रास्ता छोड़कर सही रास्ता अपना सकें।

सूरत शहर में अपराध को रोकने और अपराध में शामिल अपराधियों को सही राह पर ले जाने के लिए सूरत पुलिस आयुक्त अजय कुमार तोमर द्वारा एक पहल की गई है। अब जब दिवाली का त्योहार शुरूहो गया है तो पुलिस ने शहर में अपराध रोकने के लिए पिछले दिनों गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों की पहचान परेड कराई। यह परेड सूरत शहर के 36 पुलिस स्टेशनों के लगभग 1000 आरोपियों को एक जगह इकट्ठा करके आयोजित की गई थी।

सूरत शहर पुलिस ने इन सभी आरोपियों की वर्तमान गतिविधियों, आवासीय पते, कार्यस्थल का विवरण प्राप्त किया। इतना ही नहीं बल्कि इन आरोपियों को अपराध छोड़कर सही रास्ता अपनाने के लिए पुलिस कमिश्नर अजय परमार द्वारा उचित मार्गदर्शन भी दिया गया। पुलिस कमिश्नर अजय तोमर ने आरोपियों को हिदायत देते हुए कहा कि सही रास्ते पर चलने से खुशी मिलती है। प्रार्थना है कि भगवान आरोपियों को सही रास्ता दिखाने में मदद करें। सही रास्ते पर चलने वालों को पुलिस पूरा सहयोग करेगी। हम लोगों की मदद के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

पिछले दिनों 35 चेन स्नैचिंग के अपराध में पकड़े गए आरोपी आकाश भामरे ने कहा कि अपराध के रास्ते पर चलकर कुछ हासिल नहीं होता। अपराध करने के बाद परिवार से दूर रहना पड़ता है, जिससे परिजन भी दु:खी हैं। पिछली गलतियों का पछतावा है। मैं धीरे-धीरे गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूं।' मोबाइल और चेन स्नैचिंग के 35 मामलों में पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद गलती का बड़ा अफसोस है। लेकिन अब मैं धीरे-धीरे सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूं।' पुलिस की मदद से 35 अपराधों में से अधिकांश का समाधान ढूंढ लिया गया है। जबकि अन्य अपराधों का अभी निस्तारण चल रहा है। मैं असामाजिक गतिविधियों में शामिल दोस्तों की संगति से भी दूर हूं। अपराध का रास्ता छोड़कर सही रास्ता अपनाने के बाद आज वह डीजे के कारोबार से जुड़ा है। धोखाधड़ी करने के बाद जेल और पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होता है। इसलिए अपराध का तरीका अनुचित है।'' इसके अलावा अन्य आरोपियों ने भी अपने द्वारा किए गए अपराध पर पश्चाताप जताया। जहां कुछ आरोपियों ने अब अपराध छोड़कर सुधरने का संकल्प ले लिया है।

आईटी छात्रा को पाकिस्तानी नंबर से मैसेज भेजकर न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी

मॉर्फ फोटो से ब्लैकमेल,19 वर्षीय आईटी छात्रा ने कापोद्रा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत के कापोद्रा इलाके में अपनी विधवा मां और भाई-बहनों के साथ रहने वाली एक 19 वर्षीय आईटी छात्रा की नग्न तस्वीरें खींच लीं और उसे पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप संदेश भेजकर वायरल करने की धमकी दी। छात्रा इस मामले में कापोद्रा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने पर पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू की है।

जानकारी के मुताबिक सूरत के कापोद्रा इलाके में अपनी विधवा मां और भाई-बहनों के साथ रहने वाली 19 साल की खुशी (बदला हुआ नाम) फिलहाल आईटी की पढ़ाई कर रही है। कल शाम, जब वह घर पर मौजूद थी, तो उसे तीन पाकिस्तानी नंबरों से व्हाट्सएप पर नग्न तस्वीरें मिलीं, जो मुंबई में रहने वाली उसके मांमा के आधार कार्ड की फोटो और उसने अपने व्हाट्सएप डीपी में लगाई गई फोटो से छेड़छाड़ कर मोर्फ करके न्यूड फोटो बनाई गई थी।

तस्वीरों के साथ लिखा था, ये गांडू अपने लोन का पेमेंट नहीं कर रहा है, इसको बोल लोन का पेमेंट करे वरना तेरा न्यूड पिक वायरल हो रहा है। खुशी ने तुरंत मुंबई मामा को कॉल किया और उन्हें वही मैसेज मिला जिसमें लोन चुकाने के लिए कहा गया था। जब उन्होंने मुंबई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की तो मुंबई पुलिस ने जांच की और पता चला कि उनकी मेल आईडी हैक हो गई है। आज कापोद्रा थाने में शिकायत दर्ज कर पुलिस ने आगे की जांच की है।

कपड़ा बाजार दिवाली त्योहार के लिए रोशनी से जगमगा उठा

सूरत सोनानी मूरत का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला आकाशी दृश्य

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत शहर में दिवाली की अद्भुत रौनक देखने को मिल रही है। शहर में दिवाली की खरीदारी हो रही है और बाजारों में भी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। शहर के रिंग रोड स्थित कपड़ा बाजार में रोशनी का मनोरम नजारा देखने को मिल रहा है। कपड़ा बाजार को रोशनी से सजाया गया है।

बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया था सूरत जैसे औद्योगिक शहर के अंदर हर त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। शहर में दिवाली का उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर की विभिन्न इमारतों को लाइटिंग से सजाया गया है, वहीं रिंग रोड स्थित कपड़ा बाजार की विभिन्न इमारतों को भी लाइटिंग से सजाया गया है और दुल्हन की तरह सजाया गया है।

उत्सवी सुरतियों का माहौल सूरती हर पल का आनंद लेने में विश्वास करते हैं और इसीलिए उन्हें त्योहार-प्रेमी लोग कहा जाता है। सूरती हर त्यौहार को खास बनाते हैं। साथ ही जब दिवाली की बात आती है तो पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठता है। बड़े-बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़ी-बड़ी इमारतों पर लगी लाइटिंग पूरे शहर को अलग बनाती है।

रोशनी से बाजार जगमगा उठा सूरत शहर की रोशनी के आकाशी दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। नजारा देखकर ही ऐसा लग रहा है कि यह सूरत शहर सोने की मूर्ति है। पूरे शहर में निजी इमारतों में दिवाली का उत्साह चरम पर है। रोशनी को देखने के लिए सुरती देर रात तक घूमते नजर आए। सूरत नगर निगम द्वारा भी सरकारी इमारतों, कार्यालयों, ब्रिज, ट्रापिक सर्कल पर विभिन्न रंगो की रोशन की है।

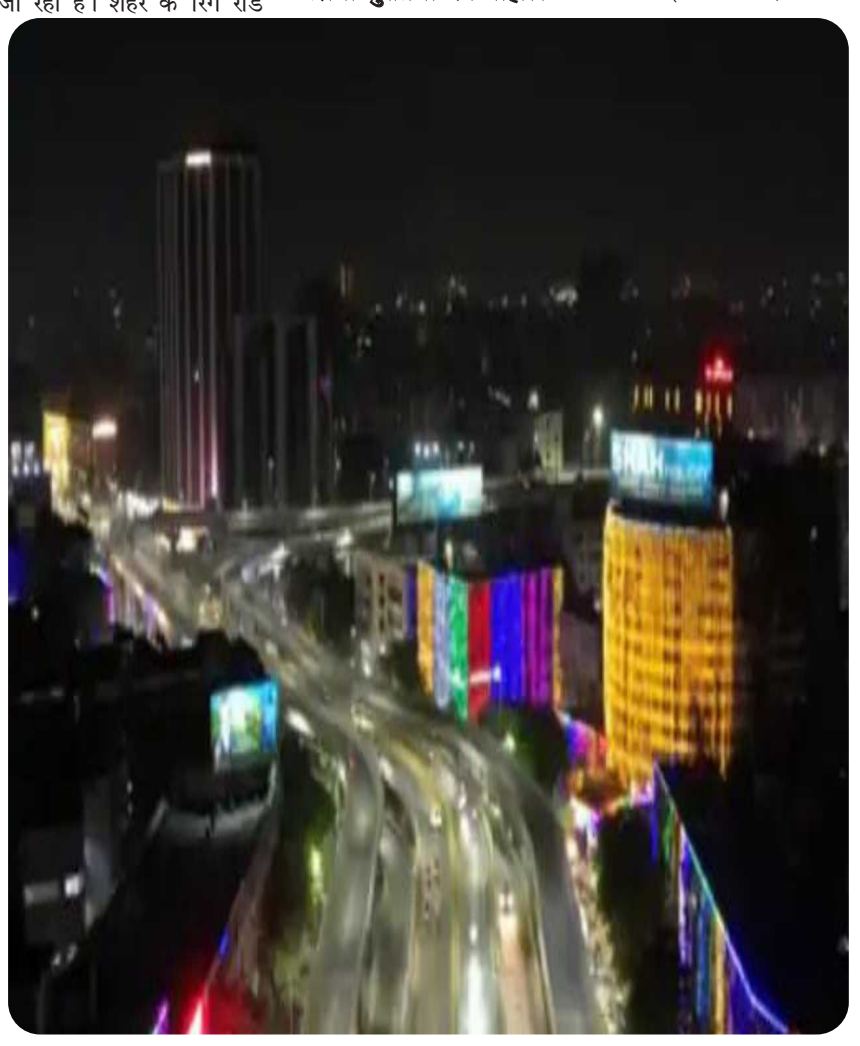

वर्ल्ड कप क्रिकेट मेच पर ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क का भंडाफोड़

कड़ोदरा पुलिस ने 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया,30 वांछित, 9.39 लाख की कीमत जब्त

पुलिस द्वारा गिरफ्तार सटोरिये और सट्टे में उपयोग होनेवाले साधन

क्रांति समय
www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

पुलिस ने सूरत जिले के कडोदरा के पास रणछोड़जी कॉम्प्लेक्स से एक सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ किया। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए 5 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि 30 से अधिक को वांछित घोषित किया गया था। 3 लाख रुपए नकद, 14 मोबाइल, कार समेत 9.39 लाख का सामान जब्त किया गया।

इस समय आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप अंतिम राऊन्ड पर चल रहा है और सटोरिये जमकर दांव लगा रहे हैं। सूरत ग्रामीण और कडोदरा पुलिस ने तलाश शुरू की। घटना यह थी कि सूरत जिले के कडोदरा स्थित रणछोड़जी कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर छह में सट्टेबाजों द्वारा ऑनलाइन सट्टेबाजी चल रही थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था। इस बीच व्हाट्सएप के जरिए वरली मटका का हार-जीत का गेम खेल कर और अन्यों को जुगार खेलाया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर कड़ोदरा पुलिस ने वहां छापा मारा। पुलिस ने पांच सट्टेबाजों को हिरासत में लिया।

कडोदरा पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा सट्टेबाजी का भंडाफोड़ किया इन पांचों के अलावा 24 अन्य लोग भी ऑनलाइन सट्टा सट्टेबाजी में शामिल थे। यहां तक कि जो लोग क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों की दौड़-भाग और मैच के एक सत्र में हार-जीत पर सट्टा लगा रहे थे। पुलिस द्वारा चिन्हित सभी 30 लोगों को पुलिस ने वांछित घोषित कर दिया है। इन दांवों पर दांव लगाने के लिए सभी को लैपटॉप के जरिए प्ले नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया था। पुलिस को यह भी चौंकाने वाली जानकारी मिली कि सॉफ्टवेयर के जरिए लाइव स्कोर पर सट्टा लगाया जा रहा था। अब कडोदरा पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़ किया है और कुछ सामान जब्त किया है। पुलिस को नौ लाख रुपये नकद, 14 मोबाइल फोन, दो टैबलेट, एक कार मिली और नौ लाख रुपये से अधिक का कीमती सामान जब्त किया गया।

यह सटोरिये पकड़े गए

बटुक बाबूभाई सोनापाल निवासी छतराला कॉम्प्लेक्स,देसाई फलिया
क्रुणाल पंकज सोनापाल निवासी बी -6 रणछोड़जी कॉम्प्लेक्स, कडोदरा
जय मुकुलभाई राणा निवासी सी - 503, सहयोग अपार्टमेंट, विधातागुण स्कूल के पीछे, अडाजण,
प्रतीक सुरेश लोढीया निवासीा बी 101, मालाबारी हाइट्स नेक्स्ट टू यूनिवर्सिटी, भटपोर, सूरत
प्रवीण केशवभाई ढीमर निवासी खाड़ी फलियु, कड़ोदरा

अपने क्षेत्र में समस्याएं हमें लिखे या बताएँ
और समस्याएं का हल संबंधित विभाग से मिलेगा
मोबाईल:-9879141 80 या फोटा,वीडियो हमें भेजे